हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

7 मार्च, 1994

खण्ड 1, अंक 6

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 7 मार्च, 1994

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रख गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(6)29
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6)30
वर्ष 1994–95 का बजट पेश करना	(6)51
वाक आउट	
वर्ष 1994–95 का बजट पेश करना (पुनरारम्भ)	(6)56

मूल्य : 108 00

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 7 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 14-00 बजे हुई । अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहिबान, अब सवाल होंगे ।

Abolition of Octroi

*657 **Shri Ram Bhajan Aggarwal :** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to abolish Octroi in the State ?

Minister of State for Local Government (Chaudhri Dharambir Gauba) : Yes, sir. There is a proposal to abolish the Octroi.

श्री राम भजन अग्रवाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस प्रोपोजल पर कब तक विचार हो जाएगा और कब तक निर्णय ले लिया जाएगा। दूसरे, इस विषय के लिए एक सब–कमेटी बनाई गई है, क्या उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी है; यदि नहीं, तो यह कब तक दी जाएगी ?

चौधरी धर्मबीर गाबा : स्पीकर सर, इस बारे में गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी उसके मैम्बर हैं, यह कमेटी इस विषय पर गौर कर रही है कि मौडैलिटिज़ को कैसे एडॉप्ट किया जाए, ऑक्ट्राय किस-किस तरह से हटाया जाए और स्टेट के फाइनैंस को कैसे ठीक किया जाए ? एक कमेटी हैडेड बाइ डायरैक्टर लोकल बॉडीज है, जिसमें एल० आर० का एक रिप्रैजेंटेटिव है और एक ऐक्साइज एण्ड टैक्सेशन का मैंबर है। उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। जब तक हाईपावर्ड कमेटी फैसला नहीं करेगी तब तक हम उस पर गौर नहीं कर सकते ।

श्री राम भजन अग्रवाल : स्पीकर सर, में आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि स्टेट के अंदर ऑक्ट्राय की मद में टोटल कितनी आमदनी होती है और उसको रिकवर करने के लिए सरकार को कितना खर्च करना पड़ता है ?

चौधरी धर्मबीर गाबा : स्पीकर सर, हमारा जो फरीदाबाद काम्पलैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ऑक्ट्राय मिलाकर 42 करोड़ रुपये की आमदनी होती है । 30 करोड़ रुपया कमेटी से मिलता है और 12 करोड़ रुपया काम्पलैक्स से मिलता है। इस 42 करोड़ रुपये के लौस को कैसे पूरा किया जाए यह कमेटी के फैसले पर डिपैन्ड करता है। ऑक्ट्राय कलैक्शन पर हमारा 30 से 40 प्रतिशत तक खर्च होता है।

श्री राम भजन अग्रवाल : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हमारी पड़ौसी स्टेटों में से किन-किन स्टेटों में ऑक्ट्राय एबोलिश कर दी गई है और क्या उन स्टेटों का अनुकरण हरियाणा सरकार करेगी ?

चौधरी धर्मबीर गाबा : स्पीकर सर, इस समय यू०पी० गवर्नमैंट ने ऑक्ट्राय एबोलिश कर रखी है । पंजाब, हरियाणा और अन्य स्टेटों में ऑक्ट्राय अभी थी है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो हरियाणा स्टेट में ऑक्ट्राय खत्म करने की बात कही है उससे हरियाणा के मुलाजिमों में एक तरह का भय है कि कहीं उनकी नौकरियां खत्म न हो जाएं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मुलाजिम इस फैसले से प्रभावित होंगे उनके बारे में सरकार क्या निर्णय लेगी।

चौधरी धर्मबीर गाबा : स्पीकर सर, 3700 मुलाजिम ऑक्ट्राय की कलैक्शन करते हैं । जो कमेटी बनाई गई है वह यह तो बताएगी ही कि फाइनैंस रिसौर्सिज कैसे ठीक हो सकते हैं साथ ही इस बात की रिकमैंडेशन भी भेजेगी कि उन 3700 मुलाजिमों को हम कैसे ऐडजस्ट कर सकते हैं । इन कर्मचारियों को निकालने का सवाल ही नहीं है ।

श्री राम भजन अग्रवाल : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आजकल जो रेट ऑफ ऑक्ट्राय है वह तर्कसंगत है या नहीं हैं क्योंकि यह किसी पर बहुत ज्यादा व किसी पर बहुत कम है ?

श्री अध्यक्ष : यह सप्लीमैंटरी मेन क्वैश्चन से रिलेट नहीं करती।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऑक्ट्राय से स्टेट को कुल कितनी आमदनी होती है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो अभी बता दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो एक कमेटी बनाई हुई है, जिसके चेयरमैन बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उसकी रिपोर्ट कब तक आ

जाएगी और क्या उस रिपोर्ट के आने से पहले भी इसे एबोलिश करने पर गौर किया जा सकता है ?

चौधरी धर्मबीर गाबा : स्पीकर सर, जो हाई पावर्ड कमेटी है, उसकी अभी एक मीटिंग हुई है। मुख्यमंत्री जी के साथ वह मीटिंग अटैन्ड करने मैं भी गया था। अभी तो हाई पावर्ड कमेटी भी फैसला करेगी। हमने स्टेट लेवल पर जो कमेटी बनाई हुई है, उसका जब तक हमारे पास ब्यौरा न आ जाए कि उन आदमियों को कैसे ऐडजस्ट करें, उससे पहले हम ऑक्ट्राय कैसे हटा सकते हैं ?

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी यह बताया है कि म्युनिसिपैलिटी के 3700 कर्मचारी ऐसे हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। इनमें से ब्यौरेवार बतायें कि क्लास-I के कितने, क्लास-II के कितने, क्लास-III के कितने तथा क्लास-IV के कितने मुलाजिम हैं। इसके अलावा, फरीदाबाद काम्पलैक्स के इसमें कितने कर्मचारी हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह सूचना तो इनके पास अभी तैयार नहीं होगी। आप बैठिये।

Upgradation of Schools in the State

*665 **Prof. Chhattar Singh Chauhan** : Will the Minister for Education be pleased to state whether any schools have been upgraded in the State during the year 1993-94, if so, the location thereof and the criteria adopted for the upgradation ?

Education Minister (Shri Phool Chand Mulana) : Yes, Sir. The list of such schools is placed as Annexure A and B on the Table of the House. The criteria adopted has been the need of the area.

ANNEXURE—A

Upgraded Schools during the Year 1993-94

Sr. No.	Name of the School	Upgraded to the level of
1	2	3
1.	G. P. S. Dhani, Raju (Hissar)	Middle Standard
2.	G.P.S. Banri (Karnal)	—do—
3.	G.P.S. Shubhri (Ambala)	—do—
4.	G.P.S, EBS Ghora Farm, Hissar	—do—
5.	G.G.P.S. Chakar (Sirsa)	—do—

1	2	3
6.	G.M.S. Chakan (Sirsa)	High level
7.	G.P.S. Patuhera (Rewari)	Middle Standard
8.	G.G.P.S. Samespur (Bhiwani)	—do—
9.	G.P.S. Rampura (Bhiwani)	—do—
10.	G.P.S. Jewra (Hissar)	—do—
11.	G.M.S. (Jewra (Hissar)	High Level
12.	G.P.S. Mahu (Gurgaon)	Middle Standard
13.	G.M.S. Mahu (Gurgaon)	High Level
14.	G.P.S. Khapar (Jind)	Middle Standard
15.	G.G.P.S. Boroda (Jind)	—do—
16.	G.M.S. Kulana (Hissar)	High Level
17.	G.M.S. Garnala (Ambala)	—do—
18.	G.M.S. Sultanpur (Ambala)	—do—
19.	G.M.S. Bhusali (Karnal)	—do—
20.	G.M.S. Ahmedpur Darewala Godekan (Sirsa)	—do—
21.	G.M.S. Karnauli (Hissar)	—do—
22.	G.M.S- Alipur Khalsa (Karnal)	—do—
23.	G.M.S. Ludesar (Sirsa)	—do—
24.	G.M.S. Kwartan (Kaithal)	—do—
25.	G.M.S. Panihar Chak (Hissar)	—do—
26.	G.M.S. Shahpur (Jind)	—do—
27.	G.H.S. Barara (Ambala)	Sr. Sec. Level
28.	G.G.H.S. Sindhvi Khera (Jind)	—do—
29.	G.H.S. Sarai Khawaja (Faridabad)	—do—
30.	G.G.H.S. Adampur (Hissar)	—do—
31.	G.H.S. Salwan (Karnal)	—do—
32.	G.H.S. Kirtan (Hissar)	—do—
33.	G.G.H.S. Nuran Khera (Sonepat)	—do—

List of 6 Schools those were allowed to start w.e.f. July, 1993, but the Financial sanction has not been issued so far

1.	G.G.H.S. Indri (Karnal)	Sr. Sec. Level
2.	G.G.H.S. Bhanswal Kalan (Sonepat)	—do—
3.	G.G.H.S. Mokhra (Rohtak)	—do—
4.	G.P.S. Kharainti (Rohtak)	Middle Standard
5.	G.P.S. Bassai (Mohindergarh)	—do—
6.	G.M.S. Bassai (Mohindergarh)	High Standard

ANNEXURE—B

Sr. No.	Name of village & Distt.	Earlier status	Upgraded status
1	2	3	4
1.	Achina (Bhiwani)	GGHS	GGSSS
2.	Mangali (Hisar)	GGHS	GGSSS
3.	Mulana (Ambala)	GGHS	GGSSS
4.	Budli Badli (Rohtak)	GGMS	GGHS
5.	Kanina Mandi (M. Garh)	GGMS	GGHS
6.	Badopal (Hisar)	GGMS	GGHS
7.	Siswal (Hisar)	GGMS	GGHS
8.	Bhupnia (Rohtak)	GGMS	GGHS
9.	Akheri Madanpur (Rohtak)	GGMS	GGHS
10.	Rawalwas Khurd (Hisar)	GGMS	GGHS
11.	Jui Khurd (Bhiwani)	GGMS	GGHS
12.	Devrala (Bhiwani)	GGMS	GGHS
13.	Gujarwas (M. Garh)	GGMS	GGHS
14.	Atta (Panipat)	GGMS	GGHS
15.	Dhatrath (Jind)	GGMS	GGHS
16.	Asadpur Nandnaur (Sonepat)	GGPS	GGMS
17.	Kuleri (Hissar)	GGPS	GGMS
18.	Matan (Rohtak)	GGPS	GGMS
19.	Khara Barwala (Hisar)	GGPS	GGMS

[Shri Phool Chand Mulana]

1	2	3	4
20.	Gorchhi (Hisar)	GGPS	GGMS
21.	Siswala (Hisar)	GGPS	GGMS
22.	Neoli Kalan (Hisar)	GGPS	GGMS
23.	Patan Tokes (Hisar)	GGPS	GGMS
24.	Silani (Rohtak)	GHS (Co.-Edu.)	GSSS (Co.-Edu.)
25.	Mandona (Ambala)	GHS (Co.-Edu.)	GSSS (Co.-Edu.)
26.	Sahlawas (Rohtak)	GHS (Co.-Edu.)	GSSS (Co.-Edu.)
27.	Badhra (Bhiwani)	GHS (Co.-Edu.)	GSSS (Co.-Edu.)
28.	Bewar Khana (Rohtak)	GPS (Co.-Edu.)	GMS (Co.-Edu.)
29.	Gandhi Nagar Mangali (Hisar)	GPS (Co.-Edu.)	GMS (Co.-Edu.)
30.	Dinar Pur (Ambala)	GPS	GMS
31.	Rampur (Ambala)	GMS	GHS
32.	Sewan Majra, Barara (Ambala)	GPS	GMS
33.	Saha (Ambala)	GGHS	10+2
34.	Ugala (Barara) (Ambala)	GHS	10+2
35.	Nagla Jattan (Ambala)	GMS	GHS
36.	Sardaheri Barara (Ambala)	GPS	GMS
37.	Gokal Garh, Barara (Ambala)	GHS	10+2
38.	Milak Khas, Bilaspur (Ambala)	GPS	GMS
39.	Pabnawa (Kaithal)	GGMS	GGHS
40.	Pharal (Kaithal)	GGMS	GGHS
41.	Tagra Hakimpur, (Block Kalka)	GPS	GMS
42.	Karanpur, Block Kalka	GHS	GSSS
43.	Kheran Wali (Block Kalka)	GPS	GMS
44.	Dhamla, Block Kalka	GPS	GMS
45.	Ram Garh, Panchkula Block	GHS	GSSS
46.	Jant (Rewari)	GMS	GHS

प्रो० छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में अपग्रेडेशन के लिये यह कहा है "the criteria adopted has been the need of the area" अगर अपग्रेडेशन के लिये क्राइटेरिया नीड आफ दी एरिया ही है, तो मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से एक बात जानना चाहता हूं । मेरी कांस्टीच्यूएंसी में दो ऐसे मिडल स्कूल हैं । एक बडसेरा का और दूसरा सांवड़ का है । हम इस बारे में मंत्री महोदय से कई बार प्रार्थना भी कर चुके है । वहां पर एक हजार से ऊपर बच्चों की संख्या है वहां के लोगों ने कालेज के बराबर बिल्डिंग बनाई हुई है । इसके अलावा, कुछ ऐसे प्राईमरी स्कूल्ज भी हैं जहां पर 500 से ऊपर विद्यार्थी है, क्या यह नीड आफ दी एरिया नहीं है ? क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो नीड आफ दी एरिया है, यह पोलीटीकल है या लोगों की मांग के अनुसार हैं ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राजनीति शब्द को बीच में ले लिया है । अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में हम इतने फार्वर्ड हैं कि एक किलोमीटर की परिधि में तो प्राइमरी स्कूल्ज हैं । किसी बच्चे को एक किलोमीटर से ज्यादा प्राईमरी शिक्षा के लिये चलना नहीं पड़ता । 2.33 किलोमीटर से फालतू मिडल, हाई और हायर सैकेन्ड्री स्कूल के लिये चलना नहीं पड़ता । अगर कहीं पर स्कूल्ज अपग्रड कराने की आवश्यकता होती है तो हम एग्जामिन कराते हैं और इस बारे में विधायक सुझाव भी देते हैं । तभी स्कूल्ज अपग्रेड किये जाते है ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय ने अपने जवाब में 33 उन स्कूलों की लिस्ट दी है जिनके बारे में फाईनैंशीयल सैंक्शन ग्रान्ट कर दी गयी है लेकिन 46 विद्यालय ऐसे भी दिये हैं जिनमें अभी यह देनी बाकी है। अध्यक्ष महोदय, इस लिस्ट में अम्बाला और हिसार, दो जिलों का ही नाम ज्यादा है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो यह लिस्ट है, इसमें महेन्द्रगढ़ जिला रिवाड़ी जिला और रोहतक जिले का नाम ही नहीं है । क्या आने वाले साल में इन जिलों में जो कमी रह गयी है, उसको रिकवर करने के लिये इनको प्राथमिकता देंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय राम बिलास शर्मा जी ने हिसार और अम्बाला जिले की चर्चा की है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हिसार वह जिला है जिसमें महिलाओं की जो परसेंटेज आफ लिट्रेसी है, वह काफी कम है । That is only 32.10% which is very much low. There is one more district, Jind, in which this percentage is lower than that of Hisar. But in Hisar itself it is very much on the lower side. The Hon. Member himself would see from the list that mostly the girls schools have been upgraded and so far as Ambala district is concerned, this is hilly district. वहां के लोग बैकवर्ड हैं ।

[श्री फूल चन्द मुलाना]

उनकी आवश्यकता थी इसलिये वहां पर स्कूल अपग्रेड किये हैं। महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी जिले में कमी की जो बात इन्होंने कही है उसके बारे में बात यह है कि जैसे ही हमारे पास साधन उपलब्ध होंगे, हर जिले की आवश्यकता को ध्यान में रखा जायेगा।

डा० राम प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि क्षेत्र/हल्के की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए स्कूल अपग्रेड हुए हैं। अध्यक्ष महोदय सारे कुरुक्षेत्र जिले में कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। बड़े बड़े कस्बे जैसे पीपली है, लाडवा है और उभरी जो बहुत बड़ा गांव है। इन सब में प्लस टू की सुविधा गांव के और शहर के लोगों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्पीकर साहब शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने वाला है। क्या इस क्षेत्र की जरूरत को ध्यान में रखते हुए वहां पर स्कूलों को अपग्रेड करने की मन्त्री महोदय कृपा करेंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि कुरुक्षेत्र जिले में कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया है और वह जिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा में सब से पहले अगर कोई विश्वविद्यालय खुला था तो वह कुरुक्षेत्र में खुला था। जहां तक स्कूलों का सवाल है जैसा कि मैंने पहले बताया है कि दो किलोमीटर या अढ़ाई किलोमीटर से फालतू बड़े से बड़े स्कूल के लिए हमारे किसी बच्चे को चलना नहीं पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, बजट, सदन के सामने आ रहा है और बजट में जितना पैसा स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए रखा जाएगा उस के हिसाब से माननीय सदस्य के विचार को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को अपग्रेड करेंगे।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि दो या अढ़ाई किलोमीटर से अधिक किसी बच्चे को नहीं चलना पड़ता। अगर चार किलोमीटर तक कोई स्कूल मेरे क्षेत्र में अपग्रेड न हुआ हो तो क्या वहां पर स्कूल अपग्रेड करने पर विचार करेंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : माननीय सदस्य अगर कोई ऐसा केस नोटिस में लाएंगे तो अवश्य ध्यान दिया जाएगा।

चौधरी बलवंत सिंह मेना : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि लड़कियों के स्कूलों को अपग्रेड करने में प्राथमिकता दी जाती है। मेरे क्षेत्र में इसमाइला एक गांव है, वहां पर लड़कियों का स्कूल है जिसमें प्लस टू के लिए कमरे बने हुए हैं। इस समय लड़कियों को प्लस टू के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। इसी तरह से चुलाना गांव एक जगह है वहां भी यही स्थिति है। क्या मन्त्री महोदय इन जगहों को प्राथमिकता देकर वहां के स्कूलों को अपग्रेड करने की कृपा करेंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा सरकार लड़कियों को बहुत ही महत्व देती है क्योंकि एक लड़की को शिक्षा देने का मतलब है कि एक परिवार को शिक्षित करना । अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं आवश्यकता होगी वहां पर हम प्राथमिकता देकर लड़कियों के स्कूल को अपग्रेड करेंगे ।

चौधरी अजमत खां : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो लिस्ट सदन में रखी है उसको देखने से पता लगता है कि हिसार में नौ स्कूल अपग्रेड किए हैं और करनाल तथा अम्बाला में चार-चार स्कूल अपग्रेड किए है परन्तु फरीदाबाद और गुड़गांव में एक एक किया है । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि लड़के और लड़कियों के स्कूलों को अपग्रेड करने का क्या क्राईटेरिया रखा है और क्या उस क्राईटेरिया को सरकार पूरा कर रही है ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने लिस्ट पढ़ी नहीं है । इस लिस्ट में हिसार है, करनाल है, रिवाड़ी है, भिवानी है, जींद है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत है । हमने लड़कों के स्कूल भी अपग्रेड किए हैं और लड़कियों के भी किए है लेकिन लड़कियों के ज्यादा अपग्रेड किए हैं और जहां एरिया की नीड है वहां लड़कों के स्कूल भी अपग्रेड किए हैं ।

चौधरी अजमत खां : स्पीकर साहब, हिसार में नौ स्कूल अपग्रेड किए हैं, अम्बाला में चार किए हैं और सिरसा में चार अपग्रेड किए हैं, गुड़गांव में दो किए हैं और दरअसल वह एक ही जगह है माहू । फरीदाबाद में एक स्कूल अपग्रेड किया है और कैथल शहर में किया है । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या दूसरी जगहों में स्कूल अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, जहां आपने अपग्रेड नहीं किए हैं, क्या सरकार वहां स्कूल अपग्रेड करेगी ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं आवश्यकता है और जो एरिया की नीड है उसको पूरी तरह से एग्जामिन करवाया है और आगे भी करवाएंगे । जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि लड़कियों के हुए हैं लड़कों के स्कूल अपग्रेड नहीं हुए हैं । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले बजट में जितना प्रावधान सदन करेगा उसके मुताबिक स्कूल अपग्रेड करेंगे ।

श्री सतबीर सिंह कादियान : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में कुल कितने स्कूल अपग्रेड किए और 23-3-1991 को जो 350 स्कूल अपग्रेड किए गए थे, उनमें से कितने स्कूलों को अपग्रेड करने का अमली जामा पहनाया गया था ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, सातवें फाइव ईयर प्लान में हमारा टारगेट केवल पांच सौ स्कूलों को अपग्रेड करने का था लेकिन हमने पांच सौ दस

[श्री फूल चन्द मुलाना]

स्कूल अपग्रेड किए । माननीय सदस्य ने पूछा है कि डिफरैन्ट सालों में कितने स्कूल अपग्रेड किए, उस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 1991-92 में 29 स्कूल प्राईमरी से मिडल अपग्रेड किए, 63 स्कूल मिडिल से हाई अपग्रेड किए और 72 स्कूल हाई से प्लस टू अपग्रेड किए । 1992-93 में प्राईमरी से मिडल स्कूल 56, मिडल से हाई 63 और 30 हाई से प्लस टू अप-ग्रेड किये गये हैं । साथ में इन्होंने कहा कि जिनका दर्जा अप-ग्रेड किया गया है, क्या उनको सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं । स्पीकर साहब जिनको अभी अप-ग्रेड किया गया है उनकी क्लासिज अप्रैल से शुरू होंगी और जो स्कूल्ज पहले अपग्रेड कर दिये गये हैं उनकी क्लासिज शुरू कर दी गई हैं ।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया कि स्कूल्ज अप-ग्रेड करते वक्त पोलिटीकल क्राईटेरिया नहीं देखा जाता लेकिन यह जो लिस्ट है, यह साबित करती है कि हिसार और अम्बाला जिलों में स्कूल्ज की अपग्रेडेशन सब से अधिक हुई है । इस से साफ जाहिर होता है कि स्कूल्ज को अप-ग्रेड करते वक्त आम लोगों की जरूरियात को नजर अन्दाज कर दिया गया है और पोलिटीकल क्राईटेरिया को ही आधार माना गया है । मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि 1991-92, 1992-93, व 1993-94 में भिवानी जिले में लड़के और लड़कियों के कितने स्कूल्ज अप-ग्रेड किये गये हैं ? साथ में इन्होंने यह भी कहा कि लड़कियों के स्कूलों की तरफ सरकार ने खास ध्यान दिया है । गवर्नमैंट मिडल स्कूल बहेसर, गवर्नमैंट मिडल स्कूल सांवड़, जिनकी अपनी बिलडिंग्ज भी है और कालेज के समान हैं । लगभग 1000 के करीब बच्चे भी वहां पर हैं, क्या ऐसे स्कूलों के लिए सरकार का जो क्राईटेरिया है, वह लागू नहीं होता है ? क्या सरकार इन स्कूलों को भी उसी क्राईटेरिया के तहत नापेगी ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर हिसार और अम्बाला जिलों की काफी चर्चा हुई है कि सारे हरियाणा के अन्दर इन दो जिलों में स्कूल्ज को सब से ज्यादा अप-ग्रेड किया गया है । हिसार जिला के मुताल्लिक इनके दिल में इसलिए सन्देह हो रहा है, क्योंकि वह मुख्य मन्त्री का जिला है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है । हिसार जिला हरियाणा के अन्दर सब से बड़ा जिला है जिसमें 10 असैम्बली हल्के हैं । इसी तरह से अम्बाला जिला भी बहुत बड़ा जिला है, उसमें भी लगभग इतनी ही असैम्बली सीटें हैं । मेरा इतना ही कहना है कि जो जिला ऐजूकेशन के लिहाज से पिछड़ा हुआ हो, उसका खासतौर से ध्यान रखा जाता है । वैसे किसी जिला के साथ सरकार कोई भेदभाव की नीति नहीं बरतती है ।

Family Planning Programme

*678 **Shri Jai Parkash** : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether any financial assistance has been received from the Central Govt. to implement the family planning programme in the State during the years 1992-93 and 1993-94 todate ; togetherwith the measures adopted by the Govt. to make the family planning programme a success ; and

(b) whether the target ; if any, fixed for the purpose has been achieved; if so, upto what extent ?

स्वास्थ्य मंत्री : (श्रीमती शान्ति देवी राठी) : वान्छित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

सूचना

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम को चलाने के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है । वर्ष 1992-93 में 2864.11 लाख रुपये की धन राशि प्राप्त हुई थी (1643.27 लाख नकद, 431.91 लाख वस्तुओं के रूप में तथा 788.93 लाख रुपये विश्व बैंक परियोजना के अधीन) वर्ष 1993-94 के दौरान अब तक (जनवरी, 1994) 2435.49 लाख रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है। इसमें 799.84 लाख जो विश्व बैंक परियोजना के अधीन मिले हैं, भी सम्मिलत हैं ।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

1. यह कार्यक्रम स्वैच्छिक रूप से लागू किया जा रहा है।
2. सभी जिलों के जनसंख्या के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं ।
3. अस्थाई तथा स्थाई तरीकों की सुविधाएं उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामान्य हस्पतालों में उपलब्ध है।
4. विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ को छोटे परिवार के नार्म अपनाने के लिए लोगों को मार्ग-दर्शन कराने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया गया है ।
5. लोगों को छोटे परिवार के लिए प्रेरित करने के लिए सभी विभागों से सहयोग लिया जा रहा है ।

[श्रीमती शान्ति देवी राठी]

6. शहरी जनता की देखभाल के लिए 37 पोस्ट पार्टम केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

7. मैडिकल कालेज रोहतक में डाक्टरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

8. राज्य में स्वैच्छिक तथा गैर सरकारी संस्थाओं को इस कार्य में भागीदार बनाने के लिए राज्य में स्टैडिंग कमेटी आन वालन्टरी एक्शन (स्कोवा) बनाई गई है।

9. 1000 जनसंख्या से अधिक वाले सभी गांव में महिला स्वास्थ्य संघ बनाए गए हैं जो कि योग्य दम्पत्तियों को छोटे परिवार के लिए प्रेरित करते हैं। राज्य में 2346 महिला स्वास्थ्य संघ कार्यरत हैं।

10. वर्ष 1981 की जनगणना अनुसार जिला भिवानी, जहां पर जन्मदर सभी जिलों से अधिक था परिवार कल्याण सेवाएं तथा मातृ एवं शिशु सेवाओं को सुधारने के लिए एक विशेष स्कीम (सोशल सेफटी नैट स्कीम) चालू की गई है।

11. बच्चों के बचाव के लिए और माताओं के स्वास्थ्य के लिए सभी बच्चों तथा माताओं को टीके लगाए जा रहे हैं।

(ख) इस कार्यक्रम के लक्ष्य तथा प्राप्तियां निम्न प्रकार से हैं :—

1992-93

तरीके	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशतता
बन्धीकरण	104000	98047	94.3
लूप निवेषण	183000	133133	72.8
निरोध प्रयोगकर्त्ता	500000	427577	85.5
गर्भ निरोधक गोलियों की प्रयोगकर्त्ता	37000	31461	85.0

1993-94

जनवरी 1994 तक

तरीका	लक्ष्य	प्रोपोशनेट लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
बन्धीकरण	110000	83600	78871	94.3
लूप निवेषण	183000	139080	110292	79.3
निरोध प्रयोगकर्त्ता	637000	530830	380146	71.6
गर्भनिरोधक गोली प्रयोगकर्त्ता	50000	41670	30962	74.3

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री महोदया ने सदन की पटल पर जो सूचना रखी है, उसी के सन्दर्भ में, मैं आपके द्वारा उन से यह जानना चाहता हूं कि जो पैसा भारत सरकार व वर्ल्ड बैंक की सहायता से राज्य सरकार को मिला है उसमें कितना-कितना पैसा जिला वाईज अलौट किया गया है और कितना-कितना पैसा खर्च हुआ है ?

श्रीमती शान्ति देवी राठी : स्पीकर सर, जितना पैसा केन्द्र सरकार व वर्ल्ड बैंक से मिला था वह सारा जनसंख्या के आधार पर सभी जिलों में आबंटित कर दिया गया है।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री महोदया ने बताया कि जनसंख्या के आधार पर पैसे का आबंटन कर दिया गया है। मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए केवल जनसंख्या के क्राईटेरिये को आधार माना गया है या कि किसी और बात को भी इसके लिये सरकार ने आधार माना है ?

श्रीमती शान्ति देवी राठी : अध्यक्ष महोदय, परिवार नियोजन केवल मात्र जनसंख्या का आधार ही होता है और उसी हिसाब से पैसा अलौट किया जाता है।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि जो पैसा हमें भारत सरकार से और वर्ल्ड बैंक की सहायता से मिला है उस के हिसाब से जनसंख्या दर में कितने परसन्टेज की कमी आई है ?

श्रीमती शान्ति देवी राठी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जनसंख्या दर में कमी का सवाल है, उसमें कुछ कमी आई है लेकिन यह कमी कम है। हरियाणा के हालात को देखते हुए यह कमी बहुत कम है। मैं यह समझती हूं कि इसमें और ज्यादा कमी आनी चाहिये थी हमारे हरियाणा के अन्दर बच्चियों की शादी कम उमर में कर देते हैं जिसकी ऐवरेज 17.8 है और भारत सरकार की 18.8 है। एक प्रान्त केरल ऐसा है जिसकी 21 दशमलव कुछ है। इसके लिए कुछ दूसरे दो तीन कारण और भी हैं। हर व्यक्ति के मन में चाह रहती है कि जहां उसके बेटी हुई है बेटा भी हो। हमारे समाज की कुछ ऐसी विचारधारा बन गई है। स्पीकर साहब, इस बारे में थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। आप जानते है कि जिस वक्त परिवार नियोजन लागू हुआ था तो हमारे हरियाणा में ही कितनी हाहाकार मची थी और उससे कुछ सरकारें भी तथा कुछ व्यक्ति विशेष भी प्रभावित हुए थे। लेकिन आज मैं यह दावे के साथ कह सकती हूं कि परिवार नियोजन जिस तेजी से चल रहा है और युद्ध स्तर पर चल रहा है उसको सभी जानते हैं। आज हमारे बुद्धि जीवी, उच्च और मध्यम वर्ग के लोग पूरी तरह से परिवार नियोजन को अपना चुके हैं, चाहे स्थाई या अस्थाई तरीके से। आज केवल एक कोताही बाकी है, वह है साक्षरता की, विशेष तौर पर हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं। उन के मन में एक चाह रहती है कि बच्चे ज्यादा हों और उनमें लड़का अवश्य हो। इसके अतिरिक्त हम लापरवाही बरतते हैं कि जो साधन नव दम्पतियों को इसके लिए बताए जाते हैं उनको अपनाने के

[श्रीमती शान्ति देवी राठी]

लिए या प्रयोग करने के लिए वे कोताही बरतते हैं। यह एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए स्थिति कन्ट्रोल नहीं हो रही है। यह कमी भी ग्रामीण क्षेत्रों में है। हमारा स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरे उपाय कर रहा है जिससे हम जल्द से जल्द इस पर और कन्ट्रोल कर पाएं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय मैं बहिन जी से कहना चाहता हूं कि देश और प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या की भीड़ एक विस्फोटक स्थिति धारण कर चुकी है। प्राय गांवों के जो नौजवान है वे हम सभी विधायकों के पास नौकरी मांगने आते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि आपके पास जमीन कितनी है तो वे कहते है कि बिल्कूल भी नहीं है। वे कहते है कि हमें या तो पुलिस में भरती करवा दें या पटवारी बना दें, हमारे 4-5 बच्चें हैं। बहिन जी ने जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम बताया है यह तो कुछ भी नहीं है। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हुं कि जिस तरह से दूसरी बातों की तरह हरियाणा ने लीड की है उस तरह से इस मामले में हम क्यों नहीं करते। चीन में फैमिली प्लानिंग बहुत भारी कामयाब हुआ है। मैं चाहता हुं कि हमारे सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाए जिसमें अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ जाएं। वह स्टडी टीम चीन में भेजी जाए और उनका सिस्टम हरियाणा में लागू किया जाए ताकि इस स्थिति पर काबू किया जाए। बढ़ती हुई जनसंख्या ला एण्ड आर्डर के लिए बड़ी भारी समस्या है और यह देश के अन्दर मौजूदा पोलिटिकल सिस्टम के सामने एक चुनौती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीन के पैट्रन पर हरियाणा के अन्दर भी इस तरह का फूल प्रूफ फैमिली प्लानिंग सिस्टम एडाप्ट करेंगे और ऐसा करके सारे देश के अन्दर मिसाल कायम करेंगे।

श्रीमती शान्ति देवी राठी : स्पीकर साहब, मेरे भाई बिसला साहब ने एक बहुत ही अच्छा और सुन्दर सुझाव रखा है। हमारे राष्ट्र के सामने बढ़ती हुई जनसंख्या की एक बड़ी भारी चुनौती है। इनकी यह बात अच्छी है। मुख्य मंत्री जी को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है कि कोई ऐसी टीम बना दी जाए, जो जिन देशों में जनसंख्या कम है उनका वह टीम सर्वे कर सकती है। मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव का स्वागत करती हूं।

प्रो० राम विलास शर्मा : स्पीकर साहब, हमारे माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह बिसला ने सदन के सामने फैमिली प्लानिंग के बारे में एक सुझाव रखा है। मैं मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि वे इस बारे में मोहम्मद इलियास, शकरुल्ला खां और अजमत खां से राय ले लें कि वे इससे सहमत हैं या नहीं। (हंसी)

श्रीमती शान्ति देवी राठी : स्पीकर साहब माननीय सदस्य राम विलास शर्मा जी ने वाकई में दुखती रग को छूआ है। हिन्दू के लिए तो यह बैन है कि वह एक ही शादी करवा सकता है लेकिन मुसलमान के लिए यह बैन नहीं है। मुसलमान चाहे जितनी शादियां करवा ले। यदि कोई आदमी शादियां ज्यादा करवाता

है तो नैचूरली उसके बच्चे भी ज्यादा ही होंगे । मैं हरियाणा वासियों से और खास करके विधायकों से अनुरोध करूंगी कि आपको इस प्रक्रिया में कम से कम काम करना चाहिए और आपका हिसाब किताब ठीक से चलना चाहिए । (हंसी)

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य भाई राम बिलास शर्मा ने जो बात छेड़ी है वह किसी और तरह से खत्म हो सकती है । मुस्लिम भाई शादियाँ चाहे तीन या चार कर लें हमें कोई एतराज नहीं लेकिन फैमिली प्लानिंग के जरिए बच्चों के बर्थ पर तो कंट्रोल किया जा सकता है । यदि मुस्लिम भाई बर्थ पर कंट्रोल कर लेते हैं तो यह समस्या अपने आप हल हो जाएगी । शादियां चाहे तीन चार कर लें लेकिन बच्चे दो से फालतू न हों । स्पीकर साहब, चूंकि अभी बिसला साहब ने जिस बात का जिकर किया था, उसमें सीरियस स्टेप्स उठाने की बात है । इनसैंटिव और डिसइनसैंटिव की बात है । जो फैमिली प्लानिंग एडौप्ट करते हैं, जिनके एक या दो बच्चे होते है उनको इनसैंटिव दिया जाए और यदि इससे ज्यादा बच्चे होते हैं तो उनको डिसइनसैंटिव किया जाए । पहले चाहे किसी के कितने ही बच्चे हैं लेकिन आइंदा से एक डैड लाईन मुकर्रर कर दी जाए कि एक या दो बच्चे से ज्यादा जिसके बच्चे हों, उनको डिसइनसैंटिव दिया जाए । क्या सरकार इस तरह की स्कीम का कोई विचार रखती है ?

श्रीमती शान्ति देवी राठी : स्पीकर साहब, भाई सम्पत सिंह जो ने जो सुझाव दिया है हरियाणा सरकार आलरेडी वह इनसैंटिव दे रही है । हमारे मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने पिछले दिनों एम्पलायड महिलाओं को जिनके दो बच्चे हैं, 6 महीने की छुट्टी देने का इनसैंटिव दिया है ताकि वे महिलाएं अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से कर सकें । अपने दूध से अपने बच्चों का पालन कर सकें । जहाँ तक इनके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, उस बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि महिलाओं में साक्षरता का अभाव है, उसको दूर करने के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने लड़कियों की बी0ए0 तक की शिक्षा फ्री की है ।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, अभी बहन जी ने कर्मचारी महिलाओं को इनसैंटिव देने के बारे में बताया है । मैं भी इनकी बात को एडमिट करता हूं कि एम्पलायड महिलाएं आलरेडी फैमिली प्लानिंग की स्कीम को एडौप्ट कर रही हैं, उनको वह इनसैंटिव दिया जा रहा है लेकिन उनसे जनसंख्या में कमी होने का कोई लम्बा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता । हमारे प्रदेश की डेढ़ करोड़ जनता में से जो महिलाएं सर्विस करती हैं उनकी संख्या तो बहुत थोड़ी है । मेरा मतलब तो उन महिलाओं को इंनसैंटिव देने के बारे में था जो आम गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, लेबर तबका है क्या सरकार द्वारा उनको कोई इनसैंटिव या डिसइनसैंटिव देने की कोई स्कीम लागू की जाएगी ।

श्रीमती शांती देवी राठी : स्पीकर साहब, देहातों में जो महिलाएं सर्विस करती है उनमें से पांच महिलाएं एक्स ओफिसिवो मैम्बर और 10 महिलाएं बिल्कुल देहाती क्षेत्र को मिला कर 15 महिलाओं की एक टीम बनाई हुई है । उनकी गांव गांव में प्रति मास बैठकें होती हैं । वह टीम अनपढ़ महिलाओं को एजूकेट करती है । व अनपढ़ महिलाओं को बताती हैं कि परिवार नियोजन के कितने फायदे हैं । कम बच्चे होंगे तो उनको अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सकता है उनका पालन पोषण सही तरीके से किया जा सकता है । वह टीम इस तरह से काम करती है ।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेन्टरी मैंने की है, उसको शायद बहन जी समझ नहीं पाई हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे सस्ते अनाज की दुकाने हैं, परमिटस देने की बात है या और किसी प्रकार के कोटे देने की बात है उनको ऐसे इनसैंटिव दिए जाएं जो आबादी को बढ़ने से रोकने में सरकार द्वारा लागू की गई पालिसी का पालन करें और जो ऐसा न करें उनको डिसइनसैंटिव किया जाए ताकि आबादी पर कन्ट्रोल पाया जा सके । मंत्री महोदया की यह बात अलग है कि प्रचार करते हैं इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पढ़े-लिखे लोग तो इन सारी बातों को समझ गए हैं और जो अनपढ़ और गरीब लोग हैं, उनमें अभी इतनी जागरूकता नहीं आई है । मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या चीन की तरह जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिये कोई इनसैंटिव व डिसइनसैंटिव की स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, सारा देश बढ़ती हुई आबादी से चिन्तित है और भारत सरकार ने इस बारे में कई दफा विचार किया है कि किस तरह बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाई जा सकती हैं, इस पर गहराई से अध्ययन चल रहा है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगनी चाहिए । यदि आबादी पर रोक नहीं लगेगी तो फिर हम चाहे कितने ही विकास के काम कर लें, उनका कोई फायदा नहीं हो पाएगा । हम पंचायत एक्ट में भी कुछ तरमीम करने जा रहे हैं और यह अमैंडमैंट इसी सैशन में ला रहे हैं । जिस प्रकार से इन्होंने चाइना का जिक्र किया, उस बारे में इनका कहना ठीक है कि चाइना ने इस पर काफी हद तक काबू पाया है । मैं भी अगले महीने चाइना जा रहा हूं, हम वहां पर देखेंगे कि उन्होंने इस बढ़ती हुई आबादी पर कैसे काबू पाया । यदि वह सिस्टम हमें ठीक लगा तो उस बारे में सबसे बातचीत करके और हाउस की सहमति से यानी असैम्बली में बात करके उसे लागू करने की कोशिश करेंगे ताकि आबादी पर कन्ट्रोल हो सके ।

Syphon on Sajuma Minor

*687. @Chaudhri Bharath Singh : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a syphon on the Sajuma Minor ; and

(b) if so, the time by which the above said syphon is likely to be constructed ?

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) ;

(a) Yes.

(b) The work shall be taken up in hand immediately subject to availability of funds.

श्री सतबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय मन्त्री महोदय ने न तो जवाब 'हां' में दिया न 'ना' में दिया है। दूसरी तरफ कहते हैं कि धन की उपलब्धि पर यह काम किया जायेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से स्पेसिफिक समय पूछना चाहता हूं कि इस साईफन का काम एक साल में या दो साल में यानी कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? ये कोई टाइम बाउंड समय बता दें।

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि धन की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि वर्ष 1994-95 में इसके लिए सिंचाई विभाग फण्डज ईयर मार्क कर रहा है। इसको हम 1994-95 में बना देंगे।

Vacant Posts of Patwaris

*670 **Shri Karan Singh Dalal** ; Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any post of Patwaris are lying vacant as at present in district Faridabad ; if so, the number thereof togetherwith the time by which the said posts are likely to be filled up ?

राजस्व मंत्री (श्री निर्मल सिंह) : हां जी, इस समय पटवारियों के 105 पद रिक्त है, जिन्हें भरने में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि जिला फरीदाबाद में 105 पटवारियों के पद रिक्त पड़े हैं। जब अकेले जिला फरीदाबाद में 105 पद पटवारियों के रिक्त पड़े हैं तो फिर सारे हरियाणा में तो पता नहीं कितने पद रिक्त होंगे ? पटवारियों के रिक्त पद होने के कारण गांव और शहर के

@Put by Shri Satbir Singh Kadian.

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

लोगों को अपनी जमीन से संबंधित पेपर लेने में बहुत अधिक कठिनाई हो रही है। दूसरे मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस मौजूदा सरकार ने पीछे 540 पटवारी, जो लगे हुए थे, उनको हटा दिया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या पटवारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए, इन निकाले हुए पटवारियों को दुबारा नौकरी में लेने पर सरकार विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि अगर मन्त्री महोदय यह समझते हैं कि पटवारियों की भर्ती में दो साल का समय लग जाएगा तो दो वर्ष का समय बहुत ज्यादा है, इसलिए एम0 ए0 या बी0 ए0 पास नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या उनमें से कुछ को पटवारियों के पदों पर लगाने बारे सरकार विचार करेगी ? स्पीकर साहब, हो सकता है इसमें सरकार को बहुत भारी समस्या हो। स्पीकर साहब, पटवारियों की भर्ती सारी स्टेट में हुई है और एक-एक लाख रुपये की बोली इन पोस्टों के लिए लगी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या पटवारियों की पोस्टस भरने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री निर्मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि जो पटवारी भर्ती किए गए थे, उनको सरकार ने हटा दिया, इसके जवाब में मैं बताना चाहूंगा कि 465 पटवारियों की नियुक्ति सरकार ने नहीं बल्कि सुप्रीमकोर्ट ने इस बात पर रद्द कर दी है कि एक ही क्षेत्र के ज्यादा लोगों की भर्ती की गई थी इसलिए शक पैदा होता है कि जो भर्ती की गई है, वह कायदे-कानून के मुताबिक नहीं की गई है। स्पीकर साहब इस बारे में सरकार ने काफी नर्मी का रवैया बरतते हुए री-एडवर्टिजमैंट में, इन लोगों को एज में रिलैक्सेशन दे कर इन्टरव्यू पर बुलाये जाने का मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही जो एम0 ए0 या बी0 ए0 पास बच्चे हैं, उनसे पटवारियों का काम नहीं लिया जा सकता। हम पटवारियों की सिलक्शन तो महीने दो महीने में करवा लेंगे लेकिन जो 2 वर्ष का समय मैंने बताया है, वह इन पटवारियों की ट्रेनिंग का समय शामिल करके बताया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, दो साल का अर्सा बहुत ज्यादा अर्सा है और इस अर्से में बहुत से भोले-भाले लोग दफ्तरों में चक्कर काटते रहेंगे और उनको वहां पर कोई जवाब देने वाला भी नहीं मिलेगा जिसकी वजह से फील्ड में लोगों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं दोबारा मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या बी0 ए0 या एम0 ए0 पास बेरोजगार युवकों को इस काम के लिए भर्ती किया जाएगा ?

श्री निर्मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ट्रेनिंग दिए बिना किसी भी व्यक्ति को फील्ड में पटवारी नहीं

लगाया जा सकता क्योंकि उसको बहुत स्पैसिफिक नेचर का काम करना पड़ता है जैसे खसरा, फर्द, गिरदावरी आदि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको करने के लिए आदमी का ट्रेंड होना निहायत जरूरी है और बिना ट्रेनिंग के यह काम नहीं हो सकता है, किसी भी बी०ए० या एम०ए० नौजवान को बिना ट्रेनिंग के यह काम नहीं दिया जा सकता। जो दो साल का समय मैंने बताया है, उसमें ट्रेनिंग पीरियड भी शामिल है भर्ती तो हम बहुत ही जल्दी कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : जो रिटायर्ड पटवारी हैं क्या काम चलाने के लिए इनको दोबारा पटवारी लगाया जा सकता है ?

श्री निर्मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो रिटायर्ड पटवारी हैं उनको लगाने के बारे में गौर किया जा सकता है। पहले भी रिटायर्ड पटवारियों को सेवा में लिया गया था और अगर जरूरत पड़ी तो इस पर विचार कर लिया जाएगा।

Cases of Rape/Murder etc Registered in the State

*726. **Prof. Sampat Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of cases of murder, rape, kinnapping/abduction registered in the State during the year 1993-94 ;

(b) the number of cases out of those as referred to in part (a) above relating to minors and the persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes ;

(c) the number of cases out of those referred to in part (a) above in which accused have been punished; and

(d) the number of cases as referred to above which are declared untraced togetherwith the cases which are under trial in the Courts ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

भाग (क)

अपराध का शीर्ष	दर्ज हुए मुकदमें	
	1993	1994 (31-1-94)
हत्या	603	34
बलात्कार	229	16
अपहरण	315	55

उपरोक्त भाग (क) में से

[चौधरी भजन लाल]

भाग (ख)

	अवयस्क		अनुसूचित जातियों		पिछड़ी जातियों	
	1993	1994	1993	1994	1993	1994
हत्या	23	—	38	4	32	—
बलात्कार	54	5	47	1	21	1
अपहरण	47	3	28	2	24	1

भाग (ग)

	दोषी सजा हुए
हत्या	3
बलात्कार	1
अपहरण	2

भाग (घ)

	अदमपता		न्यायालय में विचाराधीन	
	1993	1994	1993	1994
हत्या	42	—	378	1
बलात्कार	1	—	189	—
अपहरण	19	—	142	1

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अपने जवाब में मुख्य मन्त्री जी ने मर्डर, किडनैपिंग, एब्डक्टिंग और रेप के फिगर्ज दिए हैं, जिसमें अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और अवयस्कों के नम्बर्ज दिए गए हैं। इसमें माइनर्ज बी० सी० और अनुसूचित जाति के मर्डर के केसिज़ 97 हैं, रेप के 129 हैं और किडनैपिंग के 105 हैं। इस प्रकार बलात्कार और अपहरण के मामलों में डिप्रेस्ट क्लास है, उनकी संख्या ज्यादा है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि मर्डर के जो 603 मुकद्दमें दर्ज हुए हैं, उनमें किलिंग्ज़ कितनी हुई है और इसमें से गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक क्राईम्ज की रोकथाम का ताल्लुक है, सरकार के भरसक प्रयास रहते हैं कि कोई भी क्राइम न हो। अध्यक्ष महोदय, यह तो आप भी जानते हैं कि आज आबादी इतनी बढ़ गई है कि क्राईम्ज़

होते हैं। यह तो इनके राज में भी होते थे और आज भी होते हैं। लेकिन हमारी सरकार के भरसक प्रयास होते हैं कि अगर कोई क्राईम होता है तो उसकी फौरन जांच हो। अध्यक्ष महोदय, हत्या के 1993 में जो केसिज हुए हैं, इनमें सारी की सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें कुल 1314 गिरफ्तार हुए हैं, चालान 1150 का हुआ है, सजा दो को हुई है, बरी 101 हुए हैं और 1047 केसिज कोर्ट में विचाराधीन हैं।

इसी तरह से बलात्कार के केसिज में 338 गिरफ्तारियां हुई हैं, 322 चालान हुए हैं, 23 बरी हुए हैं और 298 केसिज कोर्ट में पैंडिंग है। अपहरण के केसों में 394 गिरफ्तारियां हुई हैं जिनमें से से 336 चालान हुए हैं, 2 की सजा हुई है 19 बरी हुए हैं और 315 केसिज कोर्ट में पैंडिंग हैं।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि 603 हत्या के जो केसिज है, इनमें कितनी किलिंग्ज हुई हैं। दूसरे, इन्होंने कहा है कि सारे अरैस्ट कर लिए हैं और इन्होंने जो ब्यान पार्ट 'डी' में दिया है, उसके मुताबिक अध्यक्ष महोदय, ये अनट्रेस्ड ही रह गए हैं इसलिए इनमें गिरफ्तारियां कैसे हो सकती हैं ? मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि जहां पर दोषी अनट्रेस्ड हैं वहां पर गिरफ्तारियां कर ली गई हैं, क्या यह ठीक है ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये भी होम मिनिस्टर रहे हैं और इनको पता होना चाहिए कि अनट्रेस्ड किसे कहते हैं। मैं इनको बता देता हूं कि केस तो दर्ज हो गया लेकिन असलियत में वह मुजरिम नहीं है या कोई खुदकशी कर ले तो वह मुकदमा 302 के तहत दर्ज होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जितने भी केसिज हैं, उनमें सारे के सारे मुलजिम पकड़े गए हैं और उनके विरुद्ध अदालत में केस हैं।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पूछ रहा हूं कि ये जो 603 केसिज हैं उसमें कितने मारे गए हैं, यह बता दें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने जो जवाब दिया है वह इन्होंने पढ़ा नहीं है। साथ ही सम्पत सिंह जी ने टोटल किलिंग के बारे में पूछा है, वह इन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है, हम बाद में इनको भिजवा देंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय यह बहुत ही अच्छी बात है कि सारे देश के मुकाबले हमारे प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी ही नहीं बल्कि सबसे अच्छी है। लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश का जिला फरीदाबाद है, उसके साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाएं लगती हैं। जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अपहरण का धन्धा करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जिले पर पड़ता है, विशेषकर जो इन्डस्ट्रलिस्टस जिन्होंने बड़ी मेहनत से नाम रोशन किया है, जैसे श्री नन्दा हैं जिन्होंने बहुत से लोगों को रोजगार दिया हुआ है, दूसरे श्री लखानी जी हैं,

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

ये ऐसे उद्योगपति हैं जिन पर सभी हरियाणावासियों को फख्र है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे उद्योगपतियों को रोजाना चिट्ठियां आती है कि सबका अपहरण कर लेंगे या आप इतना पैसा दे दो, यह दे दो वह दे दो। जितने भी वहां पर बड़े बिजनैसमैन हैं, उनको चिट्ठियां आती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से वहां पर छोटी-मोटी घटनाएं अपहरण की होती रहती है। हमारी सरकार बधाई की पात्र है कि सरकार ने उन लोगों को सुरक्षा दी हुई है लेकिन पूरी सुरक्षा नहीं है। क्या सरकार इंडस्ट्रिलिट्स को या बिजनैसमैन को उनकी लाइफ और प्रोपर्टी सुरक्षित रखने के लिए कोई ऐसा फूलप्रूफ सिस्टम बनाने का इरादा रखती है? जैसे उत्तर पदेश में इस तरह की घटनाएं होती हैं कि किसी को एक लाख में उठा लिया, किसी को 20 लाख में उठा लिया, ऐसी घटनाएं यहां न हों। इसलिए सरकार को बौर्डर के थानों में मजबूती प्रदान करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मिसाल के तौर पर मेरे हल्के में छायसा थाना है। इसका एरिया जमुना के साथ-साथ 35 किलोमीटर लगता है। इस थाने में कोई भी ढंग की जीप नहीं है। एक जीप है, वह भी टूटी हुई है। हमने कई बार कहा है कि वहां पर एक जिप्सी दी जानी चाहिए। वह थानेदार उस टूटी हुई जीप को लेकर ही यमुना के किनारे-किनारे घूमता रहता है। इसलिए क्या सरकार बोर्डर को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए वहां ज्यादा धन, बढिया हथियार और जिप्सी वगैरह दिलवाकर थानों को मजबूत करवाएगी?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, बिसला जी ने पूछा तो कुछ नहीं है केवल सुझाव अच्छे दिए हैं। इनकी बात सुझाव के आधार पर तो ठीक हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पूरी कोशिश है कि सारे बौर्डर पर कंट्रोल किया जाए, इसलिए हमने थानों में जिप्सियां भी दी हैं और पुराने हथियारों को बदला भी है। पिछले महीने ही हमने 30 जिप्सियां दी हैं। साथ ही हमने पुलिस स्टेशन की तादाद भी बढ़ायी है ताकि बौडर मजबूत हो सके और पंजाब की तरफ से इधर उग्रवादी न आ सकें या यू0पी0 की तरफ से भी इस तरह की कोई अन्य वारदात न हो सके, इसके लिए सरकार पूरी तरह से सोचती है। अगर ऐसी कोई वारदात होती है तो हमारी सरकार ने फौरन ही अपराधियों को पकड़ा है और पकड़ती है। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि हरियाणा में अन्य दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में इस तरह के क्राईम बहुत ही कम हैं।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, देश में बहुत ही कम अपराधियों को आज तक सजा मिल पायी है। इस नाते मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उनके नोटिस में भौखड़ी गांव की घटना है? यह गांव रादौर के पास है, उस गांव में एक हरिजन नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। बलात्कार करने वाले अपराधी की बेल नहीं हो सकती पर इस केस में जमानत भी हो गयी। बलात्कार के केस में उनको जमानत पर नहीं छोड़ा जाना

चाहिए था लेकिन उनको इसलिए छोड़ दिया गया ताकि वह अन्यत्र विवाह कर सके। अध्यक्ष महोदय, इस घटना को लेकर वहां पर बहुत जन आक्रोस है।

श्री अध्यक्ष : यह तो अलग क्वेश्चन है।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं भौखड़ी गांव के केस की बात कर रहा हूं। अपराध करने वाले अपराधी को विवाह करने के लिए छोड़ दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से जमानत पर अपराधियों को छोड़ते चले गए, फिर तो कोई भी अपराधी सजा प्राप्त कर ही नहीं पाएगा ?

श्री अध्यक्ष : राम प्रकाश जी, जमानत तो कोर्ट करता है।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात ठीक है, जमानत तो कोर्ट ही करता है लेकिन जो सरकारी पक्ष है, जिसने केस दायर किया है, उनका वकील भी तो अपनी बात कहने के लिए वहां पर जाता ही होगा। वकील तो पेश हुआ ही होगा, फिर क्यों नहीं उनके वकील ने इस बात को डिफैंड किया ? इस तरह से तो अपराधी मिल मिलाकर अपना काम करते ही रहेंगे और उनके केस का कुछ भी नहीं होगा और समय के साथ-साथ उनके केस का कुछ भी नहीं होता। अपराधी बिना सजा प्राप्त किए हुए ही रह जाते हैं जैसे भूतमाजरा वाले केस में हुआ है। वह केस आज तक भी ऐसे ही पड़ा हुआ है और उसका कोई भी फैसला नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आपकी सप्लीमैंट्री मेन क्वेश्चन से रिलेटिड नहीं है। इसलिए आप बैठ जाएं।

Setting up of 132 K. V. Power Station at Munak

*711 **Shri Krishan Lal :** Will the Minister for Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. for setting up a 132 K. V. Power Station at Village Munak in Distt. Karnal during the year 1993-94 ?

Power Minister (Shri. A. C. Chaudhary) : No. Sir.

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय, से जानना चाहूंगा कि मुनक में जिस 132 के0वी0 पावर स्टेशन बनाने का निर्णय पिछली सरकार ने लिया था और जिस पर कि पिछले कई साल से मैटीरियल भी पड़ा हुआ था, अब यह मैटीरियल वहां से हटा दिया गया है। क्या सरकार इस पावर स्टेशन को बनाएगी, साथ ही इस मैटीरियल को वहां से हटाने के क्या कारण हैं ?

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर सर, मेरे भाई ने यह निराधार बात कह दी कि सामान उठ गया । वास्तव में ये अगर अपना क्वैशचन देखें तो उसका ही मैंने सीधा सा जवाब दिया था । जहां तक स्कीम का ताल्लुक है, वह आलरेडी इन-हैंड है । इस पर पांच करोड़ की इन्वैस्टमैंट होनी है । इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले कुछ महीनों में इसकी अच्छी-खासी रिपोर्ट मिल जाएगी लेकिन इसकी कंपलीशन दो साल तक संभव है ।

Leakage of Pipes

*731. **Smt. Chandravati** : Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) whether any complaint of mixing of drinking water with the sewerage water in the State has been received during the current year ; and

(b) if so, the details thereof: together with the steps taken or proposed to be taken to prevent such occurrence in future ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री राम पाल सिंह कंवर) :

(क) जी हां।

(ख) जन स्वास्थ्य विभाग ने शहरों की जल वितरण एवं मल निकास के रख-रखाव का कार्य 2.4.93 से अपने हाथ में लिया । इसके तुरन्त पश्चात् सभी शहरों में ये सर्वेक्षण कराया गया कि जो त्रुटिपूर्ण निजी पानी के कनैक्शन नालियों व मेनहोल से गुजरते हैं और स्वच्छ पानी को दूषित करने का कारण बनते हैं उनका पता लगाया जा सके। जो ऐसे सभी त्रुटिपूर्ण कनैक्शन पाये गये उनको ठीक कर दिया गया। विशेषकर शिकायतें गन्दे पानी के बारे में बहादुरगढ़, भिवानी, रोहतक और गुड़गांव से प्राप्त हुई और उनको ठीक करने की कार्यवाही शीघ्र कर ली गई। इस मामले में सतर्क सावधानी प्रयोग की जा रही है और ज्यों ही कोई त्रुटिपूर्ण पानी का कनैक्शन पता लगता है उसको बिना किसी विलम्ब के ठीक करवा दिया जायेगा ।

इसकी रोकथाम के लिए निम्नलिखित पग उठाए जा रहे हैं :—

1. रिसाव कर रही जल वितरण पाईपों को शीघ्र ही ठीक किया जाता है ताकि गन्दें पानी के बाहरी प्रवेश से कोई प्रदूषण न हो ।
2. जल वितरण व्यवस्था को पूर्णतया क्लोरिनेटिड किया जाता हैं और यह निश्चित रूप से जांच लिया जाता है कि जल वितरण प्रणाली में डाली गई क्लोरीन की मात्रा वांछनीय है ।

3. जैसा कि यह देखा गया है कि पानी का दूषित होने का कारण पुरानी जंग लगी हुई जी. आई. पाइपें हैं जो निजी पानी के कनैक्शनों में प्रयोग हुई हैं । सभी पुराने जल वितरण पाईप कनैक्शनों का पता लगाने व उनके बदलने का धमाकेपूर्ण अभियान शीघ्र ही शुरु किया जा रहा है ताकि यह पता लग सके कि दूषित पानी कहां-कहां पर है ।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर सर, इस प्रकार की गल्तियां जहां-जहां पर हैं, ये क्रिमिनल नैगलीजैंसी में आती हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जिन्होंने ये गल्तियां की हैं, क्या उनको जिम्मेदार ठहराया गया है, यदि ठहराया गया है तो उनको क्या सजा दी गई है और सरकार इसको शूलप्रूफ बनाने के लिए क्या स्टैप ले रही है ?

श्री राम पाल सिंह कंवर : स्पीकर साहब, ज्यों ही हमारे नोटिस में यह बात आई हमने अपने डिपार्टमैंट के थ्रू पता करवाया । जहां पर भी इस प्रकार के प्राईवेट कनैक्शन और नालियां गली हुई मिली हैं, उसके मालिकों को तुरंत हुक्म दिया कि इनको बदलवा लें क्योंकि प्राइवेट कनैक्शनों का पाईप कंज्यूमर सप्लाई करता है ।

श्रीमती चन्द्रावती : जनाब, मेरा सवाल यह था कि जिन्होंने क्रिमिनल नैगलीजैंसी की है क्या उनको जिम्मेदार ठहराया है और यदि गल्ती पाई गई है तो उनको क्या सजा मिली है ?

श्री राम पाल सिंह कंवर : स्पीकर सर, जैसे मैंने बताया है कि यह काम पहले म्युनिसिपल कमेटी के पास था । 2.4.1993 से हमारे महकमें के पास आया है । उसके पश्चात तुरन्त ही हमने युद्धस्तर पर प्रयास किया है । महकमें के औफिसरों को हुक्म दिया कि जहां जहां भी प्राइवेट कनैक्शन की पाइप गल गई हैं, उनके कंज्यूमर्ज को तुरंत नोटिस दें कि वे उन्हें बदलवाएं । जहां इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण पाइपें थीं, उनको फौरन ही ठीक करवाया है । इसके अलावा कुछ शिकायतों के माध्यम से भी हमें पता लगा है । कुछ त्रुटिपूर्ण पाइपें जो पाइपों के ऊपर से गई हैं, उनका तुरंत ही पता लगा लिया है और उनको तुरन्त ठीक किया जा रहा है । इसके अलावा, जो अन्डर ग्राउन्ड पाईप्स हैं, उनके बारे में भी पता किया जा रहा है कि कहां-कहां लीकेज है ।

श्रीमती चन्द्रावती : सर, मैं तो जिम्मेवारी की बात पूछ रही हूं और मंत्री महोदय दूसरा ही जवाब दे रहे है । मैं यह पूछना चाहती हूं कि जिस अफसर की जिम्मेवारी थी और जिसने यह क्रिमीनल एक्ट किया है, उसके खिलाफ नैगलीजैंसी के लिए क्या ऐक्शन लिया है । जिस किसी अधिकारी का यह क्रिमीनल एक्ट आफ नैगलीजैंसी है, उसके लिये उसको क्या सजा दी है ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह तो ऐसे ही कह रही हैं। या तो यह नाम बतायें कि इस जगह पर गड़बड़ है। (व्यवधान व शोर) जहां तक सीवरेज लगाने का सवाल है या पीने का पानी देने का सवाल है, पहले यह काम म्युनिसिपल कमेटीज के ऐरिया में म्युनिसिपल कमेटी किया करती थीं। आज से कोई 20, 20,25 या 30 साल पहले की पाईप लाईनें हैं। आपको पता है कि जब इतनी ज्यादा पुरानी पाईप हो जाती हैं तो कहीं न कहीं से लीकेज तो हो जाती है। आज यहीं पर खड़े होकर यह कहना बड़ा ही मुश्किल है कि इसके लिये किस अधिकारी का कसूर है। हो सकता है वह अधिकारी मर चुका हो या रिटायर भी हो चुका हो। बात तो यह है कि कहीं पर ताजा पाईप डली हो और उसमें लीकेज हो रही हो, तब तो हम ऐक्शन लेंगें लेकिन जहां कहीं पर पुरानी पाईप्स लगी हुई हैं और वे, अब ठीक नहीं हैं, सीपेज होने की वजह से या किसी दूसरी वजह से पंक्चर हो गयी हैं तो उनको जल्दी से जल्दी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे।

तारांकित प्रश्न सं० 733

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री अमर सिंह ढांडे सदन में उपस्थित नहीं थे।

Manually Carrying of Human Excreta

*839. Dr. Ram Parkash : Will the Minister of State for Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes be pleased to state the districtwise number of families who manually carry human excreta in the State together with the steps taken or proposed to be taken to abolish this bad custom ?

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग-कल्याण राज्य मन्त्री (चौधरी जोगिन्द्र सिंह) : श्रीमान जी विवरण विधान सभा पटल पर रखा है।

विवरण

सिर पर मैला उठाने वाले परिवारों की वर्ष 1992-93 के दौरान जिलावार संख्या निम्न अनुसार है :-

क्र० सं०	जिला	परिवारों की संख्या
1.	पानीपत	144
2.	करनाल	466
3.	सोनीपत	225

4.	जीन्द	419
5.	फरीदाबाद	727
6.	कैथल	724
7.	कुरुक्षेत्र	531
8.	अम्बाला	861
9.	सिरसा	113
10.	महेन्द्रगढ़	255
11.	रिवाड़ी	488
12.	यमुनानगर	730
13.	भिवानी	654
14.	हिसार	547
15.	गुड़गांवा	527
16.	रोहतक	360
	कुल	7771

इस प्रथा को समाप्त करने हेतु राज्य सरकार एक केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम "मेहतरों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति तथा पूनर्वास" परिपालित कर रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत मेहतरो तथा उनके आश्रितों को सम्मान–जनक धंधों में पुनर्वासित करने हेतु वित्तीय सहायता तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं ।

इसके अतिरिक्त शुष्क शौचालयों को जलयुक्त शौचालयों में परिवर्तित किया जा रहा है।

डा० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कुप्रथा को कब तक समाप्त किया जा सकेगा ? एक बात और मैं कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने जो सर्वे करवाया हैं यह जानने के लिए कि यह मैला ढोने का गन्दा काम अब तक कितने आदमी कर रहे हैं? उस सर्वे के आंकड़ों से सफाई कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं । समाचार पत्रों में तो ऐसा भी छपा था कि इस वर्ग से सम्बन्धित निर्वाचित विधान सभा सदस्य भी इससे संतुष्ट नहीं हैं । क्या मंत्री महोदय इस बारे में दोबारा कोई सर्वे करवायेंगे ? तीसरी बात जो आपने कही है कि ड्राई लैट्रीन्ज को फलश लैट्रीन्ज में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, यह अच्छी बात है। इस स्कीम का जो लाभ पहुंचना चाहिए था, वह उन तक नहीं पहुंचा है । बहुत से लोगों ने इसके लिए जो दीवार बनानी थी, वह नहीं बनाई है क्योंकि वह बनाने के काबिल नहीं हैं । इसलिए यह स्कीम पूरी नहीं हुई है। क्या सरकार इस स्कीम को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सौंपने पर विचार करेगी ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, जो सिर पर मैला ढोने की प्रथा है, वह वाकई समाज के माथे पर बड़ा भारी कलंक है। इसी बात को लेकर हमने फ्लश शौचालय की स्कीम चलायी है। हमारी यह पूरी कोशिश होगी की आठवीं पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाये। ऐसी हमारी स्कीम है। हमने इसके लिए कुछ कदम भी उठाये हैं। हम इस दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ताकि इस प्रथा को जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाये।

डा० राम प्रकाश : सर्वे के बारे में भी बतावें।

चौधरी जोगेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, बात ऐसे है कि सी० एम० साहब ने एक मीटिंग कर के इस बारे में सैंट्रल गवर्नमैंट को एक लैटर 4-2-1994 को लिखा है कि उनको ट्रेनिंग देते समय जो 150 रुपये स्टाईपैन्ड का दिया जाता है, यह बहुत ही कम है। इससे कोई भी आदमी जो इस काम को छोड़ कर दूसरे कार्य की ट्रेनिंग लेगा, अपने बाल-बच्चे पाल नहीं सकता। इस लिए हम ने उनसे यह मांग की है कि इस स्टाईपैन्ड को ज्यादा दिया जाये इसके अलावा सर्वे किये गए परिवारों के बच्चों में से लेडीज को हम आई० टी० आई० में भी कटिंग और टेलरिंग की ट्रेनिंग दिलवाते हैं। दूसरे मैम्बर्ज को दूसरी ट्रेनिंग दिलवाते हैं। एक दिक्कत और आती है कि हम तो कई बार उनके लिए लोन सैंक्शन कर देते हैं लेकिन बैंक वाले वह लोन डिस्बर्स नहीं करते। वह यह देखते हैं कि उसके कुनबे में से किसी ने पहले तो लोन नहीं ले रखा है। अगर उसके कुनबे में से किसी ने भी लोन लिया हुआ हो तो वह उसको दोबारा लोन नहीं देते। ये कमजोर लोग हैं इसलिए इनकी आर्थिक हालत सुधारनी पड़ेगी। इनकी हालत सुधारने के लिए मेहतरों तथा उनके आश्रितों को विभिन्न आय उपार्जन योजना के अन्तर्गत अनुदान, सीमान्त धन तथा बैंक ऋण के रूप में 50,000.00 रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसमें कुल योजना लागत का पचास प्रति-शत अनुदान के रूप में। अनुदान की अधिकतम सीमा दस हजार रुपए, पन्द्रह प्रतिशत सीमान्त धन के रूप में निगम द्वारा व शेष राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। इन दो बैंकों से कर्जा लेने में काफी कठिनाई आती है। इसके लिए हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक लैटर भी लिखा है।

श्री अध्यक्ष : स्टाईपैंड क्या है ?

चौधरी जोगेन्द्र सिंह : एक सौ पचास रुपए वजीफे के तौर पर ट्रेनिंग लेने वाले को दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : ट्रेनिंग आप किस चीज की देते हैं ?

चौधरी जोगेन्द्र सिंह : महिला मेहतरों तथा उनके आश्रितों को सिलाई तथा कटाई में 6 मास का प्रशिक्षण दिया जाता है। मेहतर तथा उनके आश्रितों को आवश्यक प्रशिक्षण ट्राइसेम स्कीम के अन्तर्गत निजी दुकानों तथा वर्कशाप से भी दिलाया जा रहा है।

Mr. Speaker : Question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेंज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Mallekan Minor

*749. **Shri Mani Ram Keharwala** ; Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the construction work of Mallekan Minor in District Sirsa has been stopped ; if so, the reasons thereof together with total amount incurred thereon so far, and

(b) whether there is any proposal under consideration of Govt. to restart the construction work on the said minor ?

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदीश नेहरा) :

(क) हां, मल्लेकां माईनर का निर्माण कार्य आर: डी: 60000 से आगे रोक दिया गया था क्योंकि आर: डी: 33900 से आगे कच्ची नहर जो कि रेतीले, ऊंचे-नीचे तथा ऊंचे टिब्बों में से गुजरती है, में पानी पहुँच नहीं पाया इस के अतिरिक्त नहरी पानी की पूर्ती भी पर्याप्त नहीं थी, जो कि बारूवाली माइनर की इस समय की जा रही लाईनिंग का कार्य प्रगति पर है के पूर्ण होने पर सीपेज एवं अवशोरपशन से होने वाली हानियों से बचाकर उपलब्ध हो सकेगीं इस नहर पर अब तक 39.57 लाख रुपये की राशी खर्च की जा चुकी हैं, तथा

(ख) हां बारूवाली विलिका की लाईनिंग, पूर्व निर्मित मल्लेकां माईनर की लाईनिंग पूर्ण होने तथा साथ ही पर्याप्त धन राशी की उपलब्धि पर ।

Vacant Posts of English Teachers

*828. **Shri Ram Kumar Katwal** : Will the Minister for Education be pleased to state the number of schools; if any, in which English Teachers have not been posted in the State ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : "नहीं", राजकीय विद्यालयों में इंगलिश अध्यापक का कोई पद नहीं है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Samples of Petsicides/Fertilizer.

174. Chaudhri Balwant Singh Maina : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether any permission is required by the manufacturers of other States to sell their Pesticides/Fertilizer in the Haryana State ;

(b) if so, the names of the manufacturers to whom permission has been granted during the last five years and the criteria adopted therefor ;

(c) the manufacturers-wise number of samples of Fertilizers/ Pesticides; if any taken during the period mentioned in part (b) above , and

(d) whether the samples out of those referred to in part (c) above were found snb-standard , if so, the names of the manufacturers whose samples were found sub-standard and the action taken against them ?

कृषि मंत्री (श्री हरपाल सिंह) :

(क) हां । खादों के मामलों में केवल सिंगल सूपर फासफेट तथा जिंक सल्फेट के लिए अनुमति की अवश्यकता है ।

(ख, ग) कीटनाशी दवाइयों तथा खादों के निर्माताओं के सम्बन्ध में सूचना क्रमश : तथा (घ) अनुबन्ध 1 तथा 2 में दी गई है । कीटनाशी दवाइयों तथा खादों की बिक्री की आज्ञा प्रदान करते समय उनकी गुणवत्ता का मापदण्ड ध्यान में रखा जाता है । ऐसा राज्य में किसानों को अच्छी गुणवत्ता की सामग्रियां सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है ।

Annexure—I

List of the manufacturers who were granted permission for the sale of their pesticides In Haryana State.

Sr. No.	Name of the manufacturer.	Validity
1.	M/s. Bharat Pesticides Manufacturing Company.	"
2.	M/s. Lupin Agri Chemicals (India) Ltd.	"
3.	M/s. Punjab Saltpetre Refinery.	"
4.	M/s. J & K Pesticides and Chemicals Corporation.	"
5.	M/s. Chemet Chemicals Pvt. Ltd.	4-9-93

6.	M/s. J. U. Pesticides and Chemicals Pvt. Ltd.	4-9-93
7.	Indichem.	"
8.	Tropical Agro systems Ltd.	"
9.	Jay Dee Associates (pvt.) Ltd.	"
10.	Jay Dee Chemicals.	"
11.	M/s Unique Farmaid Pvt. Ltd.	"
12.	Pesto Chem. India.	"
13.	M/s Pesticides India Ltd.	"
14.	Konkan Pesticides.	"
15.	M/s National Organic Chemical Industries Ltd.	"
16.	M/s. Gayatri Pestichem.	"
17.	M/s. All India Medical Corporation.	"
18.	M/s. Gujrat Krishi Chem. Corporation.	"
19.	M/s Ghards Chemicals Ltd.	"
20.	M/s Enzymes Pharmaceticals and Indl. Chemicals Pvt. Ltd.	"
21.	M/s E. I. D. Parry (India) Ltd.	"
22.	Bhavani Fertilizers (Regd.)	"
23.	M/s Chopal Pesticides.	"
24.	M/s Sandoz (India) Ltd.	"
25.	M/s Evergreen Pesticides	"
26.	Trillo Industries Pvt. Ltd.	"
27.	M/s Coromandel Indag Products (India) Ltd.	"
28.	M/s Agrimas Chemicals Pvt. Ltd.	"
29.	M/s Food and Allied Products.	"
30.	M/s Markfed Agro-Chemicals.	"
31.	M/s Gujrat Narmada Valley Fertilizers Company Ltd.	"
32.	M/s Agro aids Pesticides.	"
33.	M/s Scarle (India) Ltd.	"
34.	M/s Ajay Ferti. Chem. (Bombay) Pvt. Ltd.	"
35.	M/s New Chemi Industries Ltd.	"
36.	M/s United Phosphorus Ltd.	"
37.	M/s Hindustan Indesecticides Ltd.	"

[श्री हरपाल सिंह]

38.	M/s Evid and Company Chemicals Ltd.	4-9-93
39.	M/s Hoechst India Ltd.	"
40.	M/s Khatau Junker Ltd.	"
41.	M/s Shreeji Pesticides Pvt. Ltd.	"
42.	M/s National Farm Chemicals.	"
43.	M/s Rallis India Ltd.	"
44.	M/s Devidayal (Sales) Pvt. Ltd.	"
45.	M/s Sulphur Mills Pvt. Ltd.	"
46.	M/s Indian Pest Control Co.	"
47.	M/s Agromore Ltd.	30-9-93
48.	M/s Pest Control (India) Ltd.	"
49.	M/s Prakash Pulverising Mills	"
50.	M/s Monsanto Chemicals of India Ltd.	"
51.	M/s Indian Manufacturing Co.	"
52.	M/s Bharat Pulverising Mills Ltd.	"
53.	M/s Omega Agro Pvt. Ltd.	"
54.	M/s Punjab Pesticides Industrial Cooperative Society Ltd.	"
55.	M/s Crop Health Products Ltd.	"
56.	M/s Universal Agro Chemical Industries (P) Ltd.	"
57.	M/s Indofil Chemicals Company	"
58.	M/s Bharati Minerals Pvt. Ltd.	"
59.	M/s Gujrat Agro Industries Corp. Ltd.	"
60.	M/s Suvochem Industries Pvt. Ltd.	"
61.	M/s Heema Pesticides.	"
62.	M/s Singhal Pesticides Industries.	"
63.	M/s J K M B Ltd.	"
64.	M/s Montari Industries Ltd.	"
65.	M/s Kisan Chemicals.	"
66.	M/s Mascot Agro Chemicals Pvt. Ltd.	"
67.	M/s Insectidides & allied Chemicals.	"
68.	M/s Solar Pesticides Pvt. Ltd.	"

69.	M/s Universal Chemical Company.	"
70.	M/s Hindustan Pulversing Mills.	"
71.	M/s Mysore Agro, Chemical Co. Pvt. Ltd.	30-9-1993
72.	M/s Sumas Chemicals Ltd.	"
73.	M/s Atul Pesticices Pvt. Ltd.	"
74.	M/s Unikill Pestlcdes (P) Ltd.	"
75.	M/s Excell Industries Ltd.	"
76.	M/s Bayer (India) Ltd.	"
77.	M/s Atlay Laboratories Pvt. Ltd.	"
78.	M/s Avid Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	"
79.	M/s Chith Chemicals.	"
80.	M/s Sudershan Chemical Ind. Ltd.	"
81.	M/s Kissan Agro. Chemicals.	"
82.	M/s Shivalik Agro Chemicals.	"
83.	M/s Hindustan Ciba Geigy Ltd.	"
84.	M/s Cynamid India Ltd.	"
85.	M/s Gupta Chemicals Pvt. Ltd.	"
86.	M/s Apex Minerals Pvt. Ltd.	"
87.	M/s Somanil Chemicals.	"
88.	M/s Agro Industrial Chemicals Co.	"
89.	M/s Chhatisgarh Pesticides Pvt. Ltd.	"
90.	M/s Agro Chemicals.	"
91.	M/s Herbicides (India) Ltd.	"
92.	M/s Chemico Pesticides Combine.	"
93.	M/s Hindustan Antibiotics Ltd.	"
94.	M/s Pestchem & Allied Industries.	"
95.	M/s Shine Metal Industries.	"
96.	M/s Super Industries.	"
97.	M/s Gautam Udyog.	"
98.	M/s Pioneer Pesticides Industries.	"
99.	M/s BASF India Ltd.	"
100.	M/s Sasya Rakahana Industries.	"

[श्री हरपाल सिंह]

101.	M/S Meerut Agro Chemical Industries.	30-9-1993
102.	M/S President Industries	"
103.	M/S Shiv Shakti Pipe Industries.	"
104.	M/S Shaw Wellace and Co. Ltd.	"
105.	M/S Goenka Industries.	"
106.	M/S Cashew Agri. Chemicals Pvt. Ltd.	"
107.	M/S Agro Chemicals Industries.	"
108.	M/S United Pesicides.	"
109.	M/S Sunbeem Agro. Chemicals Punjab Ltd.	"
110.	M/S ICI India Ltd.	"
111.	M/S Aar Cee Crop Care Insecticides Pvt. Ltd.	"
112.	M/S Union Pesticides Pvt. Ltd.	"
113.	M/S Ventech Pesticides Ltd.	"
114.	M/S Vallabh Pecticides Mfg. Co.	"
115.	M/S Bangalore Pesticides Ltd.	"
116.	M/S Hyderabad Chemical Supplies Ltd.	"
117.	M/S Sanwin Laboratories.	"
118.	M/S Madhu Sudhan Industries.	"
119.	M/S Bharat Pesticides Industries Pvt. Ltd.	"
120.	M/S Parul Chemicals Pvt. Ltd.	"
121.	M/S K. P. Industries	"
122.	M/S Ahlawat Agro Chnmical.	"
123.	M/S Vajalukshmi Insecticides & Pesticides Pvt. Ltd.	"
124.	M/S Imkemex India Ltd.	"
125.	M/S Moti Lal Pesticides (India) Pvt. Ltd.	"
126.	M/S Siris India Ltd.	"
127.	M/S HIM Chemical India.	"
128.	M/S Agarwal Industies.	"
129.	M/S Goel Agro. Chemical (Bombay).	"
130.	M/S HIndustan Chemical Industries.	"
131.	M/S Solar Barma Chemical Ltd.	"
132.	M/S Bhaskar Agro. Chemicals Pvt. Ltd.	"
133.	M/S Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers Ltd.	"
134.	M/S Gujarat Pesticines.	"
135.	M/S Singhal Minerals Pvt. Ltd.	"
136.	M/S Patron Laboratories.	30-9-1993
137.	M/S Raashi Fertilizers Ltd.	"

138.	M/S T. Stanes and Co. Ltd.	,,
139.	M/S Modern Insecticides Pvt. Ltd.	,,
140.	M/S Goyal Chemical (India).	,,
141.	M/S Voltas Ltd.	,,
142.	M/S Insects Pesticides.	,,
143.	M/S Agro. Chemical & DE Pest Corp.	,,
144.	M/S Pioneer Products Ltd.	,,
145.	M/S Pooja Minerals & Chemicals.	,,
146.	M/S Paramount Pesticides.	,,
147.	M/S Vithaj Agri. Chemical Industries Pvt. Ltd.	,,
148.	M/S Singhal Pesticides.	,,
149.	M/S Standard Pesticides Pvt. Ltd.	,,
150.	M/S Med. Chemicals.	,,
151.	M/S New Med. Chemicals.	,,
152.	M/S Ganga Crop. Safe Pvt. Ltd.	,,
153.	M/S Amba Chemical Industries.	,,
154.	M/S Kanoria Chemicals & Industries Ltd.	,,
155.	M/S Slipest Pvt. Ltd.	,,
156.	M/S Vallabh Pesticides Pvt. Ltd.	,,
157.	M/S Lupin Agro. Chemicals (India) Ltd.	21-12-1994
158.	M/S Montari Industries Ltd.	—do—
159.	M/S NOCIL	—do—
160.	M/S Pesto Chemical India.	—do—
161.	M/S Searle (India) Ltd.	—do—
162.	M/S Singhal Pesticides Industries.	—do—
163.	M/S Hoechest India Ltd.	—do—
164.	M/S Goel Agro. Chemical (Bombay)	30-4-1994
165.	M/S MARKFED Agro. Chemicals.	31-12-94
166.	M/S Aar Cee Crop. Care Insecticides Pvt. Ltd.	—do—
167.	M/S Rollis India Ltd.	—do—
168.	M/S Unieue Farmaid Pvt. Ltd.	—do—
169.	M/S Bharat Pesticides Mfg. Co.	—do—
170.	M/S TCM & Ce. Ltd.	26-9-1994

[श्री हरपाल सिंह]

NAME OF THE MANUFACTURER TO WHOM PERMISSION IS GRANTED TO SELL THE FERTILIZERS IN THE STATE

1989-90:—

Nil

1990-91:—

(i) M/s Bharat Fertilizers Manufacturing C6m.

(ii) M/s Indo Plast Pvt. Ltd. Industrial Area, Parwanoo (H.P.)

(iii) M/s Isha Chemic is Micro Nutrients Pvt. Ltd.

(iv) M/s Chakradhar Chemicals Pvt. Ltd.

(v) M/s Ram Ganga Fertilizers Ltd.

1991-92:—

1. M/s Isha Chemicals Micronutrients Pvt. Ltd.
2. M/s Rattan Micronutrients Pvt. Ltd.
3. M/s Hind Chemicals & Fertilizers
4. M/s Shivalik Chemicals Pvt. Ltd.
5. M/s Puneet Chemicals and Mechanical Works
6. M/s Chemi Ferti.
7. M/s Indo Plast Pvt. Ltd.
8. M/s Randeep Paper Board Mills
9. M/s Pal Chemicals and Fertilizers
10. M/s Jyoti Chemicals and Fertilizers
11. M/s India Phosphate and Corbonate

1992-93:—

1. M/s Namdev Chemicals and Allied Industries
2. M/s A.J. Metals Pvt. Ltd.
3. M/s Indo Plast Pvt. Ltd.
4. M/s Defence Agro Chemicals & Fertilizers
5. M/s Kalaish Paints and Chemicals
6. M/s Sona Fine Chem. Pvt. Ltd.
7. M/s Shivalik Chemicals
8. M/s Chemifert
9. M/s Rattan Micro Nutrients Pvt. Ltd.
10. M/s Jai Shree Agro Industries Pvt. Ltd.,
11. M/s Shree Acid & Chemicals Ltd.,

1993-94

1. M/s Defence Agro Chemicals & Fertilisers
2. M/s Kailash Paints and Chemicals
3. M/s Rattan Micro Nutrients (P) Ltd.

4. M/s A.J. Metals Pvt. Ltd.,
5. M/s Sona Fine Chem. Pvt. Ltd.,
6. M/s Jai Shree Agro Industries
7. M/s Gee. Emm. Interprises
8. M/s Namdev Chemicals and Allied Industries
9. M/s Isha Chemicals & Micro nutients Pvt. Ltd.,
10. M/s Shivalik Chemicals Pvt. Ltd.,
11. M/s Pant Nagar Fertiliser Ltd.,
12. M/s Gee Ess Chemicals Fertilizers
13. M/s Indo Plast Pvt. Ltd.,
14. M/s Chemi-Fert
15. M/s Jindal Industries
16. M/s Joyti Chemicals & Fertilizers
17. M/s Him Chemicals and Fertilizers
18. M/s Gandhi Chem. Fertilizers Industries
19. M/s India Phosphate & Chemicals Manufacturing Co.,
20. M/s Rama Agro Industries
21. M/s Randeep Papers Board Mills
22. M/s Sardarh Chemi-fert Industries
23. M/s Kay Chemicals Industries
24. M/s Batar Chemi-fert (P) Ltd.,
25. M/s Bharat Fertilizer manufacturing Co.,
26. M/s Varinder Agro Chemicals Ltd.,
27. M/s Munak Chemicals Ltd.,
28. M/s Khatan Fertilizers
29. M/s Ram Ganga Fertilizers
30. M/s Shree Acid and Chemicals
31. M/s Shivalik Fertilizers
32. M/s Rallies India Ltd.,
33. M/s Indo Feed Agencies Pvt. Ltd.,
34. M/s Libra Sales Pvt. Ltd.,
35. M/s Coromendal Fertilizers Ltd.,
36. M/s Mineral & Metal Trading Corporation of India

ANNEXURE II

List of the manufacturerwise samples drawn and found sub:standard

Sr. No.	Name of the manufacturer	Samples drawn					Sub-Standard					Action Taken				
		89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	Licence cancelled	Prosecution launched	Warning		Under process
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
1.	Pesticides India		17	9	22	12	1	2	1	6		—	—	8	2	—
2.	Vimal Pesticides		—	1	—	—	—	—	1	—		—	—	—	1	—
3.	United Pesticides		7	1	4	4	—	4	—	2		1	—	7	—	—
4.	Voltas Ltd.		1	1	—	5	—	—	1	—		2	—	1	—	2
5.	National Farm Chemicals		2	4	5	5	—	1	1	4		—	—	4	2	—
6.	Kisan Agro Chemical		3	2	1	1	1	—	2	1		—	—	2	1	1
7.	Somanil Chemical		—	1	6	1	—	—	1	5		—	—	6	—	—
8.	Konkan Chemical		—	2	1	3	—	—	2	—		2	—	1	1	2
9.	Pioneer Products		—	1	2	2	—	—	1	1		—	—	2	—	—
10.	Northern Minerals		77	79	59	21	1	3	4	17		1	—	24	1	1
11.	S. N. Chemical Industries		14	23	24	5	—	1	4	3		—	—	8	—	—
12.	Crop Health Products		6	8	9	4	—	1	5	3		1	—	9	1	—
13.	Unique Farm Aid Pvt. Ltd.		6	8	14	11	—	1	—	8		6	—	15	—	—
14.	Jai Shri Agro Industries		—	1	15	19	—	—	1	5		3	—	8	1	—
15.	Singhal Pesticides		4	1	11	7	—	—	—	6		—	—	5	1	—

TOTAL SAMPLES DRAWN—1010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	Pesto Chemical India		11	16	22	19	—	1	2	1	3	—	6	2	—
17.	Parkash Pulverising Mills		—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	Golden Chemicals		—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
19.	Indian Manufacturing Co.		4	3	5	5	—	—	2	3	2	—	6	—	1
20.	Omega Agro Pvt. Ltd.		6	4	1	—	—	1	3	1	—	—	3	2	—
21.	Goenka Industries		1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	Gayatri Krishi Chemicals		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	Hyderabad Chemical Supplies Ltd.		2	2	2	10	—	1	1	—	—	—	1	1	—
24.	Crop Care		4	7	2	1	—	1	3	2	—	—	4	2	—
25.	Haryana Chemical & Pesticides		9	11	8	9	—	—	2	—	—	—	2	—	—
26.	Heema Pesticides		6	5	6	2	—	—	1	6	2	—	8	—	1
27.	Veema Chemicals		1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
28.	United Pesticides		—	4	7	4	—	—	3	—	1	—	4	—	—
29.	Gautam Udyog		—	4	5	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—
30.	Meerut Agro Chemicals		1	3	1	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—
31.	Shivalik Agro Chemicals		4	4	7	4	—	4	1	—	2	—	5	2	—
32.	Shiv Shakti Pipe Industries		7	3	8	—	—	5	3	5	—	—	11	2	—
33.	Gujrat Krishi Chemical Corpn.		6	2	5	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—
34.	H. A. and F. C.		79	38	57	138	—	—	1	2	7	—	1	2	7
35.	Jai Chemicals		27	22	19	8	—	—	3	5	1	—	6	1	2
36.	Rajhans Chemicals		—	1	7	3	—	—	—	3	2	—	4	—	1
37.	Avid & Co. Ltd.		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38.	Searle India Ltd.		7	3	20	13	—	—	—	2	6	—	4	1	3

TOTAL SAMPLES DRAWN—1010

[श्री हरपाल सिंह]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39.	Hindustan Ciba Giegy Ltd.	TOTAL SAMPLES DRAWN—1010	10	14	18	11	—	—	1	2	—	—	1	1	—
40.	Gharda Chemicals		4	10	16	15	—	1	—	2	3	—	3	1	2
41.	Hafed Pesticides		49	19	38	25	2	1	—	3	—	—	3	2	1
42.	Thakkar Chemicals		23	13	19	16	—	—	1	2	—	—	2	1	—
43.	Tropical Agro Systems		8	4	15	5	—	4	—	6	5	—	10	1	4
44.	Bharat Pesticides Mfg. Co.		—	11	16	14	—	—	3	11	1	—	13	—	2
45.	Hindustan Insecticides Ltd.		6	8	3	8	—	—	1	1	—	—	1	—	1
46.	Tas Chemicals		7	6	1	1	—	1	3	1	1	—	5	—	1
47.	Gujrat State Co. Marketing Fedration Limited.		1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48.	Kisan Chemicals (Unit of Montari)		1	8	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
49.	Cashew Agri. Chemicals		3	5	3	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—
50.	Green Gold		1	3	1	2	—	—	1	1	—	—	2	—	—
51.	BASF India Limited		2	4	6	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—
52.	Monsanto Chemical of India Ltd.		3	2	4	3	—	—	—	2	—	—	2	—	—
53.	Hoechest		9	14	23	12	—	—	1	—	1	—	1	—	1
54.	Excel Industries Ltd.		10	9	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55.	All Indiax Medical Corpn.		1	2	6	1	—	—	1	6	1	—	6	1	1
56.	Kissan Chemicals		9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47.	United Phosphorus		4	21	11	17	—	—	3	3	3	2	5	—	2
58.	Madhusudhan Industries		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59.	Swastik Chemicals & Pesticides.	TOTAL SAMPLES DRAWN — 1010	22	15	17	19	—	2	7	4	5	1	11	1	5
60.	Agromore Limited		2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—
61.	Sudershan Chemical Indust.		10	3	6	14	—	4	—	3	5	—	7	—	5
62.	I.C.I.		3	3	1	1	—	—	1	1	—	—	4	1	—
63.	Sulphar Mills Pvt. Ltd.		6	5	5	5	—	—	—	2	1	—	4	—	—
64.	E.I.D. Parry Ltd.		3	1	4	2	—	—	1	1	—	—	1	1	—
65.	Agro Chemical Industries.		1	1	1	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—
66.	Super Industries		1	3	3	1	—	1	2	2	1	—	4	—	2
67.	Sumex Chemical Ltd.		3	3	7	3	3	1	—	—	2	—	3	2	1
68.	Bayer India Ltd.		4	8	7	9	—	—	—	2	—	—	1	1	—
69.	NOCIL		41	21	39	18	—	1	—	8	1	—	6	3	1
70.	Jainsons Minerals		5	9	1	5	—	—	1	—	3	—	1	—	3
71.	Shakti Insecticides Ind.		—	5	4	8	—	—	2	3	2	—	5	—	2
72.	H.P.M.		28	22	37	20	—	—	7	17	1	—	21	1	3
73.	Plant Care Concentrates		—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
74.	Goyal Argo Industries		6	6	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—
75.	Neelam Agro Industries		6	8	2	1	—	—	2	—	—	—	1	1	—
76.	Shaw Wallace Co.		3	1	2	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—
77.	Markfed Agro Chemical		1	2	5	2	—	1	1	2	—	—	2	2	—
78.	Rallies India Ltd.		28	26	16	14	—	—	—	—	1	—	1	—	—
79.	Solar Pesticides Pvt. Ltd.		—	1	2	2	—	—	1	—	1	—	1	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80.	Atul Pesticides Ltd.		—	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81.	Kamdhanu Pesticides		—	2	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—
82.	Sain Vin Lab.		—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
83.	Agrimas Chem. Pvt. Ltd.		—	1	2	4	—	—	1	—	4	—	2	—	—
84.	Shri India Limited		3	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
85.	New Chem. Industries		6	8	10	10	—	2	3	3	6	—	11	—	—
86.	Montari Industries Ltd.		27	19	42	24	3	1	—	—	—	—	2	2	—
87.	Indian Pest Control		1	2	3	—	—	—	2	3	—	—	3	—	3
88.	Mascot Agro Chemical		8	2	5	—	1	1	2	3	—	—	6	1	—
89.	Gujrat Narmada Vally Fertilizer Ltd.		4	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
90.	Evid Co. Chemicals		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91.	Gujrat Agro Ind.		12	11	8	2	—	1	2	3	—	—	4	2	—
92.	Lupin Agro Chem.		11	9	8	9	—	1	1	1	—	—	2	1	—
93.	Gupta Chem. Pvt. Ltd.		5	7	3	4	—	1	5	1	—	—	6	—	1
94.	Indofil Chem. Ltd.		1	5	8	6	—	1	5	8	3	—	11	3	3
95.	Cynamid India Ltd.		6	7	12	3	—	1	2	1	—	—	3	1	—
96.	Bharti Minerals		6	7	7	9	—	1	3	4	3	2	8	1	—
97.	Coromandal Indag India		4	2	7	9	—	—	—	—	1	1	—	—	—
98.	Jyoti Insecticides		5	5	7	4	—	2	1	5	1	1	8	—	—
99.	B.P.M.		11	2	5	4	—	—	—	1	1	—	1	—	—

TOTAL SAMPLES DRAWN—1010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100.	Shakti Insecticides		—	5	2	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—
101.	Hindustan Chemical Industries		—	3	1	1	1	—	3	1	—	—	4	1	—
102.	Bombay Pesticides & Insecticides		—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
103.	B.L. Chemical		13	4	—	3	—	5	4	—	2	—	9	—	2
104.	Punjab Pesticides & Industrial Coop. Society		1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
105.	Herbicides India		4	3	6	3	—	1	1	2	1	—	3	2	—
106.	Agro Chemicals		2	3	6	—	—	1	—	2	2	—	3	—	2
107.	Agro Aids Pessicides		1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
108.	Sunbeam Agro Chemicals		3	1	—	—	1	1	1	—	—	—	3	—	—
109.	Insecticides & Allied Chemicals		3	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
110.	Atlay Lab. Pvt. Ltd.		2	2	1	1	—	2	1	1	1	—	2	1	1
111.	M.L. Industries		—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
112.	Sandoz India Ltd.		8	3	3	4	—	1	—	—	1	—	—	1	1
113.	Avid & Co.		—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
114.	Evid Pharmaceutical Pvt. Ltd.		4	1	5	4	—	—	—	2	—	—	1	—	1
115.	Bhaskar Agro Chemicals		1	1	2	—	—	1	1	2	—	—	3	1	—
116.	B.L. Industries, Ellaenabad		5	7	1	—	—	2	4	1	—	—	7	—	—
117.	Khatau Junkar Ltd.		1	3	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
118.	Agro Industrial Corp.		—	—	3	—	1	—	—	2	—	—	3	—	—
119.	Ajay Fertilizers (Chemicals)		2	—	2	1	—	1	—	2	1	—	3	—	1
120.	Ambachem Industries		1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—

TOTAL SAMPLES DRAWN—1010

[श्री हरपाल सिंह]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
121.	Anu Pesticides.	TOTAL SAMPLES DRAWN—1010	—	—	2	16	—	—	—	1	—	—	1	—	—
122.	Aar Cee Crop Care		—	—	2	6	—	—	—	2	1	—	2	—	1
123.	Bhagwati Minerals		—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
124.	Bharat Insecticides		5	—	9	—	1	—	—	4	—	—	3	1	1
125,	Bhopal Pesticides.		—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126.	Bangaloren Pesticides		2	—	3	3	—	1	—	2	2	—	3	—	2
127.	Bharat Rasayan Ltd.		—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—
128.	Delta Chemical Industries.		—	—	5	7	—	—	—	2	2	—	4	—	—
129.	Devi Dayal Agro Chem.		—	—	2	2	1	2	1	2	—	—	6	—	—
130.	Evergreen Industries.		—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
131.	Gayatri Pesticides		—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132.	Gujarat Pesitcides.		—	—	4	1	—	—	—	3	1	—	3	—	1
133.	Growell Agro Products.		—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134.	Dhanuka Pesticides.		—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135.	Goel Agro Chem. (Bombay)		—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—
136.	Gujrat Agro Chem.		—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—
137.	Southern Peto Chem.		—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—
138.	Sandar Mfg. Co.		—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139.	T. S. Farms & Chem.		—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140.	United India Pesticides		—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—
141.	United Pesticides		—	—	—	5	—	—	—	—	2	—	1	2	—
142.	Tuticon Alkali Chem.		—	—	—	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—
143.	Siris Chem.		—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144.	Shiphon chemicals		—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—
145.	Van-teca Pesticides		—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	1	—	1
146.	Vijay Laxmi Pesticides		—	—	—	5	—	—	—	—	3	—	1	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
147.	Haryana Pesticides		3	—	3	10	—	1	—	3	7	—	10	—	—
148.	Imkemex Industries		—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
149.	Solar Pesticides		—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150.	Indochem		—	1	—	6	—	—	—	1	4	—	3	—	2
151.	Jyoti Pesticides		—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
152.	Jayco Chemicals		—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	2	—	—
153.	J.U.P. Pesticides		—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1
154.	J. K. B. M.		1	—	3	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—
155.	Unikill Pesticides		1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
156.	Union Pesticides		1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
157.	Montari Industries		—	—	42	3	2	1	—	—	1	—	1	2	1
158.	Moti Lal Pesticides		—	—	1	3	—	1	—	—	1	—	2	—	—
159.	Khandosh		1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
160.	S. L. Allied Industries		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161.	Khaitan		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162.	P. C. M. & Co.		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163.	Rohana Polymer		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164.	Bator India		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165.	J & K Pesticides		—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
166.	Jay Dee Associates		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167.	Parkash Pulverising Mills		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168.	President Industries		—	1	4	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
169.	Paushak		—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—

TOTAL SAMPLES DRAWN—1010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
170.	Parikh Enterprises		1	—	2	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—
171.	Parul Chemicals		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172.	Camphor & Allied		2	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
173.	Goel Chemicals		1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—
174.	Universal Chemico		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175.	Pesticides Allied Industries		1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
176.	Trilo Agro Industries		2	—	6	26	—	1	—	4	20	—	24	1	—
177.	Hindustan Laboratories		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178.	Sasya Rakshan Ltd.		—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
179.	Tinal Agro Chem.		—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
180.	Universal Agro Chem.		—	—	3	1	—	—	—	3	—	—	2	1	—
181.	Vallabh Pesticides		—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182.	Duzon Agro Chemicals		3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—
183.	Sunray		1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
184.	Petro Chem.		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185.	Kishan Pesticides		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
186.	Arti Minerals		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
187.	Kisan Chem. Mfg.		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TOTAL SAMPLES DRAWN—1010

Manufacturer	Product	Drawn							
		1989-90	90-91	91-92	92-93	93-94	89-90		
							R	O	T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N. F. L.	Urea	NA	NA	335	200	195	1	1	2
KRIBHCO	—do—	NA	NA	93	134	67	19	—	19
IFFCO	—do—	NA	NA	82	138	76	7	—	7
POOL	—do—	NA	NA	NA	NA	NA	4	—	4
UNKNOWN	—do—	NA	NA	8	13	7	11	—	11
I.P.L.	—do—	NA	NA	9	34	60	—	—	—
SHRIRAM	—do—	NA	NA	85	72	23	—	—	—
CHAMBAL	—do—	NA	NA	21	24	4	—	—	—
GNFC	—do—	NA	NA	50	58	43	—	—	—
SHAKTIMAN	—do—	NA	NA	NA	NA	NA	—	—	—
SPIC	DAP	NA	NA	200	168	144	—	1	1
PPL	—do—	NA	NA	337	275	75	—	1	1
KRIBHCO	—do—	NA	NA	52	22	13	1	1	2
IFFCO	—do—	NA	NA	109	196	110	2	1	3
UOKNOWN	—do—	NA	NA	7	6	3	5	—	5
POOL	—do—	NA	NA	NA	NA	NA	1	—	—
GNFC	—do—	NA	NA	NA	1	NA	—	—	—

Sub-Standard											Action Taken						
1990-91			91-92			92-93			93-94			FIR	Pros.	Warning	PRC	Sale stopped	Under process
R	O	T	R	O	T	R	O	T	R	O	T						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2	—	2	—	—	—	5	—	4	1	1	2	—	—	2	—	—	—
10	—	10	20	—	20	13	—	11	19	—	19	—	—	—	—	—	—
6	—	6	2	—	2	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	11	6	—	6	3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—
—	1	1	—	—	—	9	—	9	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	1	—	—	—
2	—	2	3	8	11	—	2	—	5	2	7	4	—	1	—	7	1
—	—	—	9	—	9	2	3	5	2	—	2	1	—	—	—	—	2
6	—	6	—	1	1	3	1	4	3	1	4	1	1	2	—	—	—
13	—	13	5	—	5	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[श्री हरपाल सिंह]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.P.L.	DAP	NA	NA	65	56	17	—	—	—	—	—	—
PACL	,,	NA	NA	79	42	14	—	—	—	—	—	—
CHAMBAL	,,	NA	NA	NA	NA	117	—	—	—	—	—	—
HAFED	,,	NA	NA	NA	NA	226	—	—	—	—	—	—
GSFC	,,	NA	NA	78	52	91	—	—	—	—	—	—
IFFCO	NPK	NA	NA	30	59	22	13	—	13	5	—	5
HAFED	,,	NA	NA	NA	3	NA	4	—	4	11	—	11
UNKNOWN	,,	NA	NA	11	14	6	13	—	13	29	—	29
HF&C	,,	NA	NA	24	30	21	—	—	—	—	—	—
JAI BHARAT	,,	NA	NA	3	—	—	—	—	—	—	—	—
N.E.L. BHARAT	CAN	NA	NA	43	26	6	16	1	17	28	—	28
CHEMICALS	SSP	NA	NA	NA	6	1	—	5	5	—	—	—
SHRI ACID	,,	NA	NA	NA	3	6	—	1	1	—	—	—
RAM GANGA	,,	NA	NA	NA	NA	6	—	1	1	—	—	—
UNKNOWN	,,	NA	NA	NA	2	1	2	—	2	1	—	1
H.C.L.	,,	NA	NA	1	NA	3	—	—	—	2	—	2
HAFED	,,	NA	NA	NA	NA	NA	—	—	—	—	1	1
NITIN	,,	NA	NA	NA	NA	NA	—	—	—	—	—	—

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	—	1	—	1	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
2	—	2	—	—	—	—	3	3	3	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—
—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	10	2	—	2	3	—	3	—	—	—	—	—	—
—	2	2	—	10	10	10	—	6	3	2	7	5	—	1
—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	2	3	3	—	—
4	—	4	5	—	5	—	3	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	—	—	—	1
—	—	—	—	3	3	—	4	4	1	3	2	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	1	1	—	3	3	—	—	—	—	3	—	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
M/s ORINENTAL-CARBON	SSP	NA	NA	103	107	63	—	—	—	—	—	—
AGRO CHEM	,,	NA	NA	NA	4	NA	—	—	—	—	—	—
INDIA CERIOL	,,	NA	NA	78	103	27	—	—	—	—	—	—
SHIVALIK	,,	NA	NA	NA	5	1	—	—	—	—	—	—
MUNAK	,,	NA	NA	NA	4	NA	—	—	—	—	—	—
BHARAT CHEM	,,	NA	NA	NA	5	10	—	—	—	—	—	—
RAMPUR DISTIL.	,,	NA	NA	64	39	23	—	—	—	—	—	—
JAI SHREE	,,	NA	NA	37	37	4	2	—	2	1	—	1
I.P.L.	MOP	NA	NA				—	1	1	—	—	—
TATA	Zinc	NA	NA	NA	NA	NA	—	2	2	—	—	—
MAHESH	,,	NA	NA	8	1	22	—	2	2	—	—	—
TRISHUL	,,	NA	NA	NA	NA	NA	—	1	1	—	—	—
INDOPLAST	,,	NA	NA	3	2	3	—	2	2	—	—	—
GANDHI CHEM	,,	NA	NA	1	—	7	7	—	7	2	—	2
UNKNOWN	,,	NA	NA	2	1	1	—	—	—	—	2	2
HARYANA AGROCHEM	,,	NA	NA	NA	9	11	—	—	—	—	4	1
PRABHAT	,,	NA	NA	NA	30	39	—	—	—	—	1	1
B.B. CHEMICALS	,,	NA	NA	NA	NA	NA	—	—	—	—	1	1
VIKAS	,,	NA	NA	NA	NA	NA	—	—	—	—	1	1
KAILASH PAINTS	,,	NA	NA	7	4	3	—	—	—	1	—	1
JINDAL	,,	NA	NA	6	3	2	—	—	—	—	2	2

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
—	1	1	—	8	8	—	15	15	1	13	7	1	—	2
—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	2	—	1	—	—
—	—	—	1	3	4	—	1	1	—	1	2	—	—	1
—	—	—	—	3	3	1	—	1	—	—	2	1	—	—
—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
2	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—		—
—	—	—	—	—	—	—	3	3	5	—	1	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	2	—	1	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—

[श्री हरपाल सिंह]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
M/s												
JAI SHREE	Zinc	NA	NA	NA	9	11	—	—	—	—	—	—
HARYANA ZINC	,,	NA	NA	NA	1	NA	—	—	—	—	—	—
UTTAR BHARAT	,,	NA	NA	1	7	NA	—	—	—	—	—	—
SONIA OVERSEAS	,,	NA	NA	—	9	14	—	—	—	—	—	—
PARKASH	,,	NA	NA	1	4	2	—	—	—	—	—	—
RADHA	,,	NA	NA	1	1	1	—	—	—	—	—	—
INDIA PHOSPHATE	,,	NA	NA	1	9	22	—	—	—	—	—	—
ZIMIDARA	,,	NA	NA	NA	NA	NA	—	—	—	—	—	—
GEE EMM.	,,	NA	NA	NA	0	9	—	—	—	—	—	—
PARTAP HARYANA CHEM	,,	NA	NA	NA	4	1	—	—	—	—	—	—
JYOTI CHEM.	,,	NA	NA	4	3	4	—	—	—	—	—	—
BHUMI SUDHAR	,,	NA	NA	3	5	1	—	—	—	—	—	—
A.J. METAL	,,	NA	NA	NA	NA	NA	—	—	—	—	—	—
SONA FINE CHEM	,,	NA	NA	NA	2	1	—	—	—	—	—	—
CHEMI FERT	,,	NA	NA	NA	3	NA	—	—	—	—	—	—
PANT NAGAR	,,	NA	NA	NA	NA	3	—	—	—	—	—	—
RELIANCE	,,	NA	NA	NA	NA	1	—	—	—	—	—	—
AMAR PRODUCTS	,,	NA	NA	NA	NA	1	—	—	—	—	—	—
NORTHER MINERALS MICRO NUTRIENTS	,,	NA	NA	NA	NA	3	—	—	—	—	—	—

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	5	1	—	—
—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—

वर्ष 1994–95 का बजट पेश करना

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will present the Budget estimates for the year 1994-95.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, जीरो आवर है ।

श्री अध्यक्ष : आज बजट पेश होना है इस लिए आज जीरो आवर नहीं है ।

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन के सामने वर्ष 1994–95 के बजट अनुमान पेश करने जा रहा हूं ।

15.00 बजे

केन्द्र में वर्ष 1991 में कांग्रेस के सत्ता में आने के साथ ही अहम संरचनात्मक तथा आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आरम्भ हुई । ये सुधार सफल हुए और गत वर्ष अर्थ व्यवस्था की दृढ़ता व स्थिरता का वर्ष रहा । विदेशी निवेशकों ने भारत में अपनी दिलचस्पी दिखाई और भुगतान की स्थिति में बड़ा सुधार आया । उद्योग भी मन्दी की चपेट से निकला और अब इसके उभरने के आसार नजर आने लगे हैं । गत वर्ष के दौरान हर पहलू से देश ने निरन्तर प्रगति की और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय में एक नई छवि और प्रतिष्ठा बनाई ।

हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 1993-94

हरियाणा आर्थिक क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है । "हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 1993–94" की प्रतियां माननीय सदस्यों को पहले ही बांटी जा चुकी हैं, इस में राज्य की समूची आर्थिक स्थिति का वर्णन है । मूल्य सूचकांक (आधार 1980-81) के मोटे अनुमानों के अनुसार वर्ष 1992-93 में राज्य की अर्थ व्यवस्था में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वर्तमान मूल्यों पर राज्य का निवल गृह उत्पादन वर्ष 1991-92 में 14,551 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1992-93 में 16,392 करोड़ रुपये हो गया और इस प्रकार इसमें 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । तृतीयक, माध्यमिक तथा प्राथमिक क्षेत्रों में वास्तविक विकास की दर क्रमशः 7.0 प्रतिशत 4.5 प्रतिशत तथा 4.0 प्रतिशत रही । वर्ष 1992-93 के दौरान वर्तमान मूल्यों के आधार पर राज्य में प्रति व्यक्ति आय 9609 रुपये होने का अनुमान है जबकि यह आय वर्ष 1991-92 में 8722 रुपये थी ।

राष्ट्र तथा राज्य स्तर पर कीमतों की वृद्धि दर नियन्त्रण में रही । अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982-100) मार्च, 1992 में 229 से 6.1 प्रतिशत बढ़कर मार्च, 1993 में 243 हुआ और उसके बाद 9.1 प्रतिशत बढ़कर नवम्बर, 1993 में 265 हो गया । इसी प्रकार हरियाणा राज्य श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982-100) मार्च 1992 में 213 से 7.5 प्रतिशत बढ़कर मार्च, 1993 में 229 हो गया ।

[श्री मांगे राम गुप्ता]

वर्ष 1993-94 के बजट अनुमानों के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान 620 करोड़ रुपये के कुल पूंजी निर्माण का अनुमान है। इसमें 269 करोड़ रुपये का सीधा पूंजी निर्माण और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी जुटाने के लिये राज्य सरकार का योगदान 351 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

विकास नीति

जनता की आशाएं ज्यों-ज्यों बढ़ती हैं और सरकार पर विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिये दबाव बढ़ता है तो इस बात की आवश्यकता होती है कि राज्य में उपलब्ध साधनों का नए सिरे से अवलोकन करके नए साधनों को ढूंढा जाए। सरकार का यह भी अहसास है कि अर्थ-व्यवस्था का सुधार करने के लिये उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण सामाजिक दृष्टि से काफी कीमत चुकानी पड़ती है और यह सुनिश्चित करना निहायत जरूरी है कि जन साधारण और विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अथवा कमजोर वर्गों पर इनका कुप्रभाव कम से कम हो। हम यह भी समझते हैं कि जनता से सीधा सम्पर्क राज्य सरकार का रहता है, व यह सुनिश्चित करना भी राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने या साधनों में कमी होने के बावजूद विकास की प्राथमिकताएं बनी रहें व जन कल्याण की योजनाएं और राज्य का आर्थिक विकास जारी रहे। इस बजट में इन सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया है।

वार्षिक योजना 1993-94

आर्थिक रूप से चालू वर्ष अत्यन्त कठिन रहा क्योंकि अप्रत्याशित घटनाओं से साधनों में हुई कमी और खर्चे में वृद्धि ने राज्य के वित्त पर काफी बोझ डाल दिया। बाढ़ के कारण राज्य में बहुत हानि हुई। मन्दी से केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के कर राजस्व पर बुरा प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप केन्द्रीय करों के हमारे हिस्से में 24.66 करोड़ रुपए की कमी आई। बिक्री-कर की वसूली में बजट अनुमानों से 10 करोड़ रुपए से भी अधिक की कमी होने की सम्भावना है। कर्मचारियों को कई रियायतें दी गईं, जिसके परिणामस्वरूप वेतन तथा पेंशन का वित्तीय बोझ बढ़ गया। राष्ट्रीय ताप बिजली निगम तथा अन्य केन्द्रीय एजेन्सियों के प्रति कुछ बकाया राशि की अदायगी के लिए राज्य बिजली बोर्ड के लिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करनी पड़ी। इन वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद विकास की गति को बनाये रखने के लिए सरकार ने 42 करोड़ रुपए से भी अधिक के अतिरिक्त साधन जुटाए। केन्द्र से आर्थिक कर्जे प्राप्त करने के लिए अल्प बचतों में जमा राशि को बढ़ाने के प्रयास भी किए गए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बजट अनुमानों में दिए गए 125 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले में अल्प बचतों के खाते से 140 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त किए जाने की सम्भावना है। राजस्व खाते के खर्च में किफायत करके व सभी वित्तीय लेन-देन में सख्त

अनुशासन का परिचय देकर, हम बिना भारी कटौती के विभिन्न विकास योजनाएं चला पाए । बहरहाल, वर्ष 1993-94 की वार्षिक योजना के परिव्यय को 920 करोड़ रुपये से घटाकर संशोधित अनुमानों में 831.46 करोड़ रुपए किया गया जोकि वार्षिक योजना 1992-93 के 752.46 करोड़ रुपये के वास्तविक खर्च से 10.5 प्रतिशत अधिक है ।

वार्षिक योजना 1994-95

वार्षिक योजना 1994-95 तैयार करते समय आठवीं पंच वर्षीय योजना में घोषित लक्ष्यों अर्थात् सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं बढ़ाने और उनमें सुधार करने, रोजगार के अधिक अवसर बनाने, आधारभूत संरचना के विकास तथा कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के साथ-साथ आर्थिक विकास की गति को बनाये रखने पर ध्यान दिया गया है । वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद विकास की गति को कायम रखने तथा तेज करने की जरूरत महसूस करते हुए, वार्षिक योजना 1994-95 के लिए 1025.50 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। यह वार्षिक योजना 1993-94 के लिए संशोधित बजट परिव्यय से 23 प्रतिशत से भी अधिक है। सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के लिए 375.39 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो योजना परिव्यय का 36.6 प्रतिशत हिस्सा है । आधारभूत संरचना के विकास को जारी रखने के लिए कुल परिव्यय का 23.1 प्रतिशत बिजली के विकास पर, 18.2 प्रतिशत सिंचाई पर और 2.2 प्रतिशत सड़कों पर खर्च किया जाएगा। खर्च का 7.3 प्रतिशत हिस्सा कृषि और सम्बद्ध कार्यों के लिए है । राज्य सरकार अर्थ-व्यवस्था में विविधता लाने और द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रों में अंशदान बढ़ाने के लिए गहन प्रयास कर रही है ताकि अर्थ-व्यवस्था पुख्ता हो सके और इसमें आवश्यक लचीलापन आ सके। हमें विश्वास है कि चरणबद्ध ढंग से इतना भारी निवेश न केवल आर्थिक विकास की गति को बनाये रखने में बल्कि अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति को बढ़ाने और समाज के कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी सहायक होगा।

आपद् राहत

राज्य में इस वर्ष के दौरान मौसम ज्यादा अनुकूल नहीं रहा । जुलाई, 1993 के कुछ दिन लगातार वर्षा से राज्य के बहुत से भागों में भारी बाढ़ आई। पंजाब से बाढ़ का पानी आ जाने से समस्या और भी गम्भीर हो गई। 1105 गांवों तथा 13 नगरों में 4.6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र, जिसमें 1.33 लाख हैक्टेयर फसली-क्षेत्र शामिल है और 14.26 लाख लोगों पर बाढ़ का भारी असर रहा । इससे 50 व्यक्तियों और 596 पशुओं की जानें गईं । सरकार ने तुरन्त भोजन, आश्रय और चिकित्सा-सुविधा देकर राहत पहुंचाई और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया । थल सेना और वायु सेना से भी सहायता प्राप्त की गई । भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें 205.56 करोड़ रुपये केन्द्रीय राहत अनुदान मांगा गया केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1994-95 के लिए आपद् राहत निधि के केंद्रीय हिस्से से 6.38 करोड़ रुपये पेशगी दिए हैं ।

[श्री भीम सेन गुप्ता]

बाढ़ राहत उपायों के लिए 16.60 करोड़ रुपये और क्षतिग्रस्त लोक निर्माण-कार्यों के सुधार और मरम्मत के लिए 30.79 करोड़ रुपये की राशि दी गई है । मृतक व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धी को दी जाने वाली अनुग्रही राहत की राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई। पशु-हानि व मकानों के नुकासान के लिए मुआवजे तथा कृषि उपयोगी पदार्थों पर सबसिडी की दरों में भी उचित वृद्धि की गई। वित्तीय संस्थानों ने भी बाढ़-प्रभावित किसानों को राहत देने में राज्य सरकार को सहयोग दिया। किसानों के छोटी अवधि के कर्जों को मध्यम अवधि के कर्जों में बदल दिया गया। बाढ़ रोकने के उपायों के लिए सरकार ने रावी-ब्यास तथा सिकन्दरपुर नालों के निर्माण का भी निर्णय लिया है । इसके लिए 1.52 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति भी दे दी गई है। विभिन्न आपद् राहत उपायों के लिए 47 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च की गई ।

दसवां वित्त आयोग

माननीय सदस्यगण इस बात से परिचित ही हैं कि राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाने और केन्द्र से राज्यों को निधियों के अन्तरण के लिए सिफारिशें करने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा दसवें वित्त आयोग का गठन किया गया है । राज्य सरकार ने वर्ष 1995 से 2000 के दौरान करों के बंटवारे और सहायता अनुदान के लिए विस्तारपूर्वक दलीलें देते हुए आयोग के विचारार्थ ज्ञापन दे दिया है । प्रशासन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाएं भी पेश की हैं जिनके लिए उस अवधि के दौरान 2,322 करोड़ रुपये राशि की आवश्यकता होगी । हमने राज्य की विशेष समस्याओं के लिए 3,425 करोड़ रुपये के अनुदान की भी मांग की है । आयोग द्वारा विचार-विमर्श के लिए निकट भविष्य में राज्य का दौरा किया जाएगा । सम्भव है कि वे राज्य के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी भेंट करें । माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे भेंटवार्ता के समय राज्य को अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए जोरदार दलीलें पेश करें ।

73वां तथा 74वां संशोधन

माननीय सदस्यों को विदित है कि संसद द्वारा संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम बनाया गया है । देश-भर में ग्राम पंचायतों का एक समान विस्तरीय ढांचा शुरू किया जा रहा है और पंचायतों की समय-अवधि अन्य प्रजातांत्रिक संस्थाओं के समान पांच वर्ष नियत कर दी गई है । अधिनियम में महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान है । संविधान के इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्यों में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन और राज्य निधियां पंचायतों को अन्तरित करने के बारे में सिफारिशें करने के लिए राज्य वित्त आयोग, व पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया सुपरवाइज करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया

जाना है । राज्य सरकार जल्दी ही इन आयोगों का गठन करेगी । संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत इसी प्रकार का प्रावधान नगर निकायों के लिए भी किया गया है ।

बिजली

सरकार इस तथ्य के प्रति पूरी तरह जागरूक है कि आर्थिक विकास की गति को बनाये रखने के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है । चालू वर्ष के दौरान बिजली की स्थिति थोड़े समय के लिए कुछ नाजुक रही । पहले बाढ़ और फिर मानसून के दौरान लगभग सूखे के कारण भाखड़ा और पौंग परियोजनाओं से बहुत कम बिजली प्राप्त हुई । तथापि, कृषि और अन्य क्षेत्रों के लिए हरियाणा राज्य बोर्ड ने मंहगी दरों पर बिजली की खरीद राज्य के बाहर से की । इसके परिणामस्वरूप कम वर्षा के बावजूद खरीफ की फसल बहुत अच्छी हुई । आशा है, रबी फसल भी इसी प्रकार अच्छी होगी ।

माननीय सदस्यगण, आप इस बात से अवगत हैं कि कुल उपलब्ध बिजली का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा कृषि क्षेत्र को पचास पैसे प्रति यूनिट की रियायती दर पर सप्लाई किया जाता है जबकि उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने की वास्तविक लागत 1.31 रुपये प्रति यूनिट पड़ती है । उपलब्ध बिजली का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र को रियायती दरों पर सप्लाई करने के कारण बिजली बोर्ड को भारी हानि हो रही है । वर्ष 1992-93 में हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को 335.66 करोड़ रुपये की कुल कार्यशियल हानि हुई है ।

बिजली उत्पादन बढ़ाने और वितरण प्रणाली में सुधार करने के गहन प्रयास किये जा रहे हैं । अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जुटाने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है । हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा में बिजली क्षेत्र में "सुव्यवस्था एवं निवेश अध्ययन" किया जाये । इसके लिए विश्व बैंक से 20 लाख अमरीकी डॉलर कर्ज लिया जायेगा । इस अध्ययन की सिफारिशों से हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की कार्यकुशलता बढ़ाने और विश्व बैंक से बिजली के लिए पर्याप्त वित्तीय मदद प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।

वर्ष 1994-95 के दौरान बोर्ड की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए बजट में 105 करोड़ रुपये की नकद ग्रामीण बिजलीकरण सबसिडी का प्रावधान किया गया है । सरकारी विभागों से देय बकाया 425 करोड़ रुपये के बिजली बिलों का समायोजन हरियाणा बिजली बोर्ड को दिये गये कर्जों की अप्तियों के साथ किया जा रहा है । बिजली के पारेषण और वितरण नैट वर्क में सुधार लाने और पानीपत थर्मल परियोजना के छठे यूनिट को पूरा करने के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान सरकार ने बिजली क्षेत्र में 236.88 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है ।

वाक-आउट

इस समय सदन में उपस्थित जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य बजट की तथाकथित लीकेज के विरोध में वाक आउट कर गये ।

वर्ष 1994-95 का बजट पेश करना (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) :

सड़क संरचना

सरकार उद्योग एवं कृषि दोनों क्षेत्रों के समूचे विकास के लिए थल परिवहन के पर्याप्त व कुशल आधारभूत ढांचे के महत्व को समझती है । राज्य की सड़कें देश-भर में सर्वोत्तम मानी जाती हैं । जून 1991 में हमारी सरकार बनने के पश्चात् सड़कों की मरम्मत तथा देख-देख, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की फोरलेनिंग, नई सड़कों तथा पुलों का निर्माण करने तथा भविष्य में कार्यान्वित की जाने वाली नई परियोजनाएं बनाने पर जोर दिया गया । मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इन सभी पहलुओं पर प्रगति हुई है । 402 कि० मी० लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ है, विशेषत: 6,166 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर नई परत चढ़ाई गई है और 757 किलोमीटर लम्बी सड़कों में सुधार किया गया है । चूंकि सड़कों का निर्माण पूंजीगत कार्य है, अत: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को भी इस कार्य में लगाया गया है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 1 सुरथल से करनाल तक चारमार्गी बनाने के कार्य में अच्छी प्रगति हुई है और 25 किलोमीटर लम्बी सड़क को यातायात के लिए खोल दिया गया है । कुल 50 किलोमीटर लम्बी सड़क के जून, 1994 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है । करनाल-अम्बाला भाग का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा । बल्लबगढ़ से होडल तक राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 2 की फोरलेनिंग दिसम्बर, 1995 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है । गुड़गांव से राजस्थान सीमा तक राजमार्ग नं0 8 को चारमार्गी बनाने का कार्य एशिया विश्व बैंक की 160 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता से शुरू किया जाएगा । बहादुरगढ़ से रोहतक तथा आगे फतेहाबाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 10 को चारमार्गी बनाने की परियोजना अनुमोदनार्थ थल परिवहन मन्त्रालय को भेजी गई है । अम्बाला-यमुनानगर से दिल्ली तक एक नया "एक्सप्रैस हाईवे" बनाने का प्रस्ताव है । 437 करोड़ रुपये की लागत से 811 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाने की राज्य सड़क परियोजना विश्व बैंक द्वारा सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार कर ली गई है ।

गत अढाई वर्षों के दौरान 21 पुलों का निर्माण किया जा चुका है । चालू वर्ष के दौरान मारकण्डा नदी पर अम्बाला-कैथल सड़क पर जलबेड़ा में, यमुना नदी

पर करनाल-मेरठ रोड़ पर व पश्चिमी यमुना नहर पर कर्ण झील के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 1 पर पुलों के निर्माण-कार्य को पूरा कर लिया गया है । यातायात के प्रवाह को सुचारू एवं बिना रुकावट चलाने के लिए पानीपत में दो, तथा सोनीपत, बहादुरगढ़ और हिसार में एक-एक, कुल पांच ओवर ब्रिजों का निर्माण किया जा रहा है । मोरनी-त्रिलोकपुर रायपुररानी सड़क पर टांगरी नदी पर और बरोटीवाला के निकट सिरसा नदी पर पुलों का निर्माण जारी है । रिवाड़ी तथा बल्लभगढ़ में दो ओवरब्रिज बनाने का कार्य योजना स्तर पर हैं ।

सिंचाई

कृषि में लगातार वृद्धि को पर्याप्त जल उपलब्ध करवाये बिना जारी नहीं रखा जा सकता । हरियाणा में भूगत जल लगभग समाप्त होता जा रहा है । अब सिंचाई का और अधिक विस्तार मुख्य तौर पर सतलुज-यमुना लिंक नहर, जोकि राज्य की जीवन रेखा है, के पूरा होने पर निर्भर करता है । पंजाब में बिगड़े हालात के कारण नहर के निर्माण में कुछ अनावश्यक विलम्ब हुआ है । हमारी सरकार नहर के शीघ्र निर्माण के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है और हम भारत सरकार व पंजाब सरकार से इस विषय में लगातार वार्तालाप कर रहे हैं । हमें आशा है कि पंजाब में कानून और व्यवस्था में सुधार होने से नहर का निर्माण-कार्य जल्दी दोबारा शुरू होगा और शीघ्र ही पूरा हो जाएगा । उपलब्ध पानी के यथोचित इस्तेमाल के लिए सारी नहर-व्यवस्था का उचित रख-रखाव आवश्यक है । इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1994-95 के बजट अनुमानों में 14.82 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है । हरियाणा के सतलुज-यमुना लिंक नहर के हिस्से और पंजाब में सांझे जल-मार्गों के रख-रखाव के लिए भी प्रावधान किया जा रहा है ।

सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए पानी की रिसन-हानि कम करने हेतु नहरों तथा जल-मार्गों को पक्का करने की विभिन्न परियोजनाएं सिंचाई विभाग, कमाण्ड ऐरिया, विकास प्राधिकरण और लघु सिंचाई तथा नलकूप निगम द्वारा चलाई जा रही हैं । वर्ष 1993-94 के दौरान 200 लाख वर्ग फुट कच्चे जलमार्ग क्षेत्र को 35.19 करोड़ रुपये की लागत से पक्का किया जाएगा, जिससे 110 क्यूसिक जल बचेगा और 32,000 एकड़ भूमि में अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी ।

विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान "जल स्त्रोत समेकन परियोजना" नाम की एक नई परियोजना मंजूर किये जाने की सम्भावना है । इसके अन्तर्गत शेष जलमार्गों को पक्का करने, रिसन हानि को रोकने और खारे क्षेत्रों के सुधार के लिए भूगत जल निकास और जल-क्षमता को बढ़ाये जाने का लक्ष्य है । यह परियोजना 6 वर्ष की अवधि में क्रियान्वित की जाएगी और इस पर कुल 800 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । 1994-95 के दौरान, इस प्रयोजन के लिए वार्षिक योजना में 93.30 करोड़ रुपये का प्रावधान है ।

[श्री मांगे राम गुप्ता]

हरियाणा के लिए यह गर्व की बात है कि राजस्थान सरकार ने 40.21 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की सिद्धमुख-नोहर फीडर परियोजना के निर्माण के लिए हरियाणा सिंचाई विभाग की सेवाएं ली हैं। यह मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजना लगाने में हमारी तकनीकी क्षमता का सूचक है।

लघु सिंचाई के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान 30.57 करोड़ रुपये की लागत से 960 किलोमीटर लम्बे 210 जलमार्गों को पक्का किया जाएगा। इससे 6,880 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हो सकेगी। वर्ष 1994-95 के दौरान 1,136 किलोमीटर लम्बे जलमार्गों को पक्का करने के लिए 29 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार इस बात से पूरी तरह अवगत है कि केवल सिंचाई क्षमता बढाना ही काफी नहीं। अतः हम कमाण्ड एरिया के विकास को विशेष महत्व दे रहे हैं, जिसके लिए वर्ष 1994-95 की वार्षिक योजना में 25.30 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। चालू वर्ष के दौरान 23 करोड़ रुपये की लागत से 21 लाख फुट लम्बे जलमार्गों को पक्का किया जाएगा और 31,700 हैक्टेयर क्षेत्र में बाराबंदी शुरू की जाएगी। भारत सरकार के अनुमोदन से आगरा नहर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र और पश्चिमी यमुना प्रणाली के कुछ अतिरिक्त कमाण्ड क्षेत्र को भी कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत लाया गया है।

कृषि तथा सम्बद्ध कार्य

कृषि के क्षेत्र में हमारी प्रगति उल्लेखनीय रही है। वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य में खाद्यान्न की कमी थी, किन्तु अब यह देश का "खाद्यान्न भण्डार" बन गया है। माननीय सदस्यों को मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि वर्ष 1993-94 के दौरान हरियाणा राज्य ने केन्द्रीय खाद्यान्न पूल में 34.54 लाख टन गेहूं दिया। पिछले तीन वर्षों से हरियाणा राज्य लगातार भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक चावल केन्द्रीय पूल में दे रहा है। वर्ष 1993-94 में केन्द्रीय पूल के लिए नियत 7.5 लाख टन चावल के लक्ष्य के मुकाबले फरवरी, 1994 तक 11.61 लाख टन चावल दिया जा चुका है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 1993-94 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय मैंने यह विश्वासपूर्वक कहा था कि हमारा राज्य 1.00 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न पैदा करके नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। मुझे इस गरिमामय सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य वर्ष 1993-94 के दौरान 103.50 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य के मुकाबले, 105 लाख टन उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए अग्रसर है। चालू वर्ष के दौरान 7.00 लाख टन गुड़, कपास की 13 लाख गांठें और सूरजमुखी समेत 7.6 लाख टन तिलहन का उत्पादन होने की सम्भावना है।

हम किसानों को व्यापक उत्पादन आधार प्रदान करने के लिए खेतीबाड़ी में विविधता लाने के प्रयास कर रहे हैं । गन्ना, कपास और तिलहन जैसी नकद फसलों की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सूरजमुखी की काश्त को बढ़ावा दिया जा रहा है। और चालू वर्ष में 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती किए जाने की आशा है । राज्य में सोयाबीन और राजमाश की नई फसलों की खेती भी शुरू की गई है ।

मैं पहले भी यह कह चुका हूं कि मानसून के दौरान राज्य के बहुत से भाग बाढ़ से प्रभावित हुए । इससे 1.33 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों का नुकसान हुआ । बाढ़-पीड़ित-किसानों की मदद के लिए सरकार द्वारा 160 रुपये प्रति एकड़ की दर से कृषि उपयोगी वस्तुओं पर सबसिडी दी गई । इसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था । हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि-कार्यों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को राहत दी जाती है, इसमें मृत्यु की स्थिति में 30.000 रुपये और अंगहीन होने की स्थिति में 12,000 रुपये तक अनुदान दिये जाते हैं। अब तक कृषि दुर्घटना के शिकार 1,799 व्यक्तियों को 2.15 करोड़ रुपये के ऐसे अनुदान दिये गए हैं । किसानों को बीज, उर्वरकों, कीटनाशी, खरपतवार नाशक, पानी, जिप्सम और दूसरे इन्पुटों पर सीधी सबसिडी नियमित आधार पर दी जाती है । रासायनिक खादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार से प्राप्त 7.41 करोड़ रुपये की राशि किसानों को खाद पर सबसिडी के रूप में वितरित की गई है । इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप खाद की खपत 1992-93 में 6.63 लाख टन से बढ़कर वर्ष 1993-94 में लगभग 7.3 लाख टन हो गई । वर्ष 1994-95 के लिए खाद की खपत का लक्ष्य 8.18 लाख टन नियत किया गया है ।

वर्ष 1994-95 के लिए 107 लाख टन खाद्यान्न, 9 लाख टन गुड़, 15 लाख कपास की गांठें और 8.85 लाख टन तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य नियत किया गया है ।

राज्य की अनेक एजेंसियां खेतों के भूमि सुधार कार्यक्रमों में लगी हुई हैं । राज्य की खारी भूमि के सुधार के लिए 15.26 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली एक पायलट परियोजना वर्ष 1994-95 में क्रियान्वित की जाएगी । इसके लिए डच सरकार से तकनीकी और 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता मिलेगी । इस परियोजना के अन्तर्गत सोनीपत जिले में जवाहर लाल नेहरू नहर और कैथल जिले के कलायत क्षेत्र में भाखड़ा नहर के कमांड क्षेत्रों की सेम और खारेपन से प्रभावित भूमि में मशीनों से समतल भूगत निकास व्यवस्था लगाने सम्बन्धी तकनीक का अन्तरण किया जाएगा । समेकित वाटर शैड विकास (पहाड़ी) परियोजना, काण्डी क्षेत्र की मार्च 1990 से अम्बाला और यमुनानगर जिलों की तराई में 1.92 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के समेकित विकास के लिए चलाई जा रही है। इस परियोजना के लिए वर्ष 1993-94

[श्री मांगे राम गुप्ता]

के लिए 4.60 करोड़ रुपये और 1994–95 में 5.30 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है । हरियाणा भूमि सुधार तथा विकास निगम भी रियायती जिप्सम के वितरण और भूमि समतलन आदि द्वारा भूमि सुधार कार्यों में लगा हुआ है ।

कृषि–उत्पादन में हो रही असाधारण वृद्धि के दृष्टिगत आवश्यक भण्डारण और विपणन नैट वर्क की व्यवस्था का महत्व भी बढ़ गया है। हरियाणा वेयर हाऊसिंग निगम कुल 9.6 लाख टन क्षमता के 104 भण्डारणगृह चला रहा है। वर्ष 1993–94 के दौरान इस क्षमता में 5.670 मीट्रिक टन और 1994–95 में 9,000 मीट्रिक टन की बढ़त की जाएगी । हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मार्केट यार्ड, खरीद केन्द्र और लिंक सड़कों के निर्माण से राज्य में फसल मार्केटिंग नैट वर्क को सुदृढ़ बना रहा है । 100 मुख्य यार्ड, 175 उप यार्ड तथा 135 खरीद केन्द्र बन चुके हैं जिससे किसान को अपने गांव के 5 से 7 किलोमीटर घेरे के अन्दर ही फसल बेचने की सुविधा उपलब्ध है ।

बागवानी

वर्ष 1990 में अलग बागवानी निदेशालय बनने और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में विविधता आने से बागवानी विकास अब गतिशील हो गया है। वर्ष 1990 के पश्चात् राज्य में सब्जियों तथा फलों की काश्त के अधीन क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है । खुम्भी उत्पादन, फूलों की खेती और ड्रिप सिंचाई तथा पालीग्रीन हाऊस जैसी नई तकनीकों को शुरू करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

पशुधन विकास

हमारा विश्वास है कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के एकीकृत विकास के लिए पशुधन का विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है । अतः हम पशु-चिकित्सा हस्पतालों और डिस्पैंसरियों के व्यापक नैट वर्क के माध्यम से नस्ल सुधार, संतुलित भोजन और असरदार स्वास्थ्य रक्षा जैसे पशुपालन कार्य करने पर जोर दे रहे हैं । 7 जिलों में एकीकृत पशु विकास परियोजना लागू की जा रही है । 536 पशु चिकित्सा हस्पतालों, 762 पशु-चिकित्सा डिस्पैंसरियों, 60 क्षेत्रीय कृत्रिम वीर्य सेचन केन्द्रों और 758 स्टाकमैन केन्द्रों के वर्तमान पशु स्वास्थ्य नैट वर्क को, 200 नई पशु-चिकित्सा डिस्पैंसरियां खोलकर और 10 पशु-चिकित्सा डिस्पैंसरियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें हस्पताल एवं प्रजनन केन्द्र बनाकर सुदृढ़ किया जाएगा । गुड़गांव में एक पालीक्लिनिक भी खोला जाएगा । इस क्षेत्र के लिए वर्ष 1994-95 में 6.33 करोड़ रुपये की योजनागत व्यवस्था की गई है ।

सहकारिता तथा उधार

माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि कृषि तथा सम्बद्ध कार्यों को बढ़ावा देने में सहकारिता आन्दोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । राज्य की सहकारी

वित्त संस्थाएं किसानों एवं लघु तथा छोटे ग्रामीण उद्योग की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है । राज्य की विभिन्न सहकारी संस्थाओं ने पहली अप्रैल, 93 से 31 दिसम्बर, 93 तक 660.37 करोड़ रुपये के फसल कर्ज, 32.21 करोड़ रुपये के गैर-कृषि कर्ज, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा ग्रामीण कारीगरों के लिए 123.01 करोड़ रुपये के कर्ज और कृषि विकास के लिए 67.29 करोड़ रुपये के लम्बी अवधि के कर्ज दिए । कर्जों की वसूली में भी सुधार हुआ हैं और विभिन्न संस्थाओं में 62.5 प्रतिशत से 77.7 प्रतिशत तक वसूली हो रही है । वर्ष 1993-94 के दौरान बाढ़ से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए सहकारी बैंकों ने 28.44 करोड़ रुपये के छोटी अवधि के कर्जों को मध्यम अवधि कर्जों में बदल दिया । वर्ष 1994-95 के दौरान सहकारिता क्षेत्र के लिए योजना पक्ष में 4.88 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं ।

उद्योग

आर्थिक प्रगति के लिए उद्योगीकरण अनिवार्य है । राज्य के तीव्र उद्योगीकरण के लिए सरकार ने अनेक नीति निर्णय लिये हैं । पहली अप्रैल, 92 से नई औद्योगिक नीति अपनाई गई थी जिसमें कृषि-आधारित खाद्य संसाधन उद्योगों और इलक्ट्रानिक उद्योगों को थ्रस्ट एरिया माना गया है । पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए जनरेटर सैटों के लिए सबसिडी देने के अतिरिक्त बिजली शुल्क और चुंगी से छूट, बिक्री-कर से छूट तथा आस्थगन और मूल्य प्राथमिकता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं । विदेशी तथा प्रवासी भारतीय निवेश जुटाने के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया गया है । राज्य को ऐसे 246 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 176 औद्योगिक प्लाट प्रवासी भारतीयों को अलाट किये गये हैं, 33 यूनिटों में उत्पादन-कार्य शुरू हो चुका है।

संतुलित क्षेत्रीय उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 76 विकास खण्डों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है। औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में 10 औद्योगिक सम्पदाएं और 2 विकास केन्द्र स्थापित किए जाएंगे । चालू वर्ष के दौरान, 160 करोड़ रुपये के निवेश से 45 बड़े तथा मध्यम औद्योगिक यूनिट और लघु क्षेत्रों में 6422 यूनिट लगाए गए थे । अनेक उद्यमकर्ताओं ने हरियाणा में परियोजनाएं स्थापित करने हेतु भारत सरकार को औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन दिए है । इनमें से 117 यूनिट चालू हो चुके है और 107 यूनिट चालू होने वाले हैं । गुड़गांव में जापान की सहायता से एक भाडल औद्योगिक टाउनशिप स्थापित किया जाएगा । उन्नत तकनीकी और प्रदूषण रहित उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है ।

इलैक्ट्रानिक्स के विकास के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान 3.08 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय का उपबन्ध किया गया है । पंचकूला में भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटिड के लिए इलैक्ट्रानिक्स सहायक खण्ड स्थापित किया गया है। यू0एन0डी0पी0

[श्री मांगे राम गुप्ता]

की सहायता से स्थापित की जा रही "प्रिसिजन मैकेनिकल डिजाइन एण्ड असिस्टिड फैसिलिटीज" परियोजना के अन्तर्गत पर्याप्त प्रगति हुई है । गुड़गांव में एक इलैक्ट्रानिक सिटी स्थापित करने के सम्बन्ध में संतोषजनक प्रगति हुई है और 32 फ्लैटिड फैक्ट्री माड्यूल का निर्माण पूरा हो चुका है ।

पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगीकरण के लिए, भारत सरकार ने राज्य में दो विकास केन्द्र स्थापित करने की स्कीम अनुमोदित की है । इन विकास केन्द्रों का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में बिजली, पानी, दूर संचार आदि आधारभूत सुविधाएं देकर वहां उद्योगीकरण को बढ़ावा देना है । इन दो विकास केन्द्रों को स्थापित करने की जिम्मेदारी हरियाणा राज्य औद्योगिक उद्योग विकास निगम को सौंपी गई है ।

राज्य के गांवों में 'उद्योग कुंज नामक लघु विकास सम्पदाओं का भी विकास किया जा रहा है । शुरू में ऐसी सम्पदाएं गुड़गांव, सोनीपत, हिसार और रोहतक के चार जिलों में स्थापित की जाएंगी । वर्ष 1994-95 के दौरान उद्योग के लिए 27.64 करोड़ रूपए का योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

औद्योगिक वित्त संस्थाएं

हमें विश्वास है कि उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहनों और रियायतों की व्यवस्था करने के साथ-साथ सुदृढ़ आधारभूत ढांचा तथा वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण है, जिसकी व्यवस्था प्रभावी वित्तीय संस्थानों द्वारा की जाती है । हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, हरियाणा राज्य वित्त निगम, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिकस विकास निगम तथा हरियाणा कृषि-उद्योग निगम, ये चार संस्थाएं उद्योगों को ईक्विटी भागीदारी तथा मध्यम एवं लम्बी अवधि के कर्जों के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं । वर्ष 1993-94 के दौरान हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने नई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्राइवेट पार्टियों के साथ 10 समझौता ज्ञापन-पत्रों और 11 वित्तीय सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिन में 8.28 करोड़ रुपए की ईक्विटी भागीदारी होगी और कुल 196 करोड़ रुपए का निवेश निहित होगा । निगम ने उपकरणों की पट्टेदारी का भी कार्य शुरू कर दिया है और यह पहली राज्यस्तरीय संस्था है जिसे मर्चेन्ट बैंकर के रूप में भारतीय स्टाक एक्सचेंज बोर्ड द्वारा प्रथम कैटेगरी का प्राधिकार दिया गया है । भावी उद्यमकर्ताओं को राज्य में सभी सुविधाएं एक स्थान पर ही जुटाने हेतु निगम किराया-खरीद तथा बिलों के हुण्डावन की सेवा प्रदान करने की योजना भी तैयार कर रहा है । हरियाणा वित्त निगम ने दिसम्बर 1993 तक 86.38 करोड़ रुपए के सावधि ऋण मंजूर किए हैं और वर्ष 1994-95 के दौरान 200 करोड़ रुपए के कर्ज मंजूर करने व 162 करोड़ रुपए के कर्ज वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा कृषि उद्योग निगम ने कृषि पर आधारित तथा खाद्यान्न संसाधन के यूनिट स्थापित करने के लिए 6 समझौता ज्ञापन पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं ।

सार्वजनिक उद्यम

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में 48 उद्यम विभिन्न विनिर्माण, व्यापार, सेवा कल्याण तथा वित्तीय गतिविधियों में संलग्न हैं। हरियाणा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों की वित्तीय क्षमता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोई भी सार्वजनिक उपक्रम इस ब्यूरो की पूर्व स्वीकृति के बिना अतिरिक्त पदों का सृजन अथवा अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन नहीं कर सकता। ब्यूरो इन उद्यमों के कार्य को मानीटर करता है और उनकी समीक्षा करता है। इसने महत्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटरों के आंकड़ा आधार तैयार किए हैं।

संस्थागत वित्त तथा राज्य ऋण योजना

संस्थागत वित्त राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में विशेष भूमिका निभाता है। वर्ष 1993-94 में राज्य की वार्षिक ऋण योजना में 1,217.6 करोड़ रुपए के ऋण की परिकल्पना है जोकि गत वर्ष की ऋण योजना से 29.7 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1992-93 के दौरान हरियाणा में वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं ने 1,347.35 करोड़ रुपए के ऋण दिए जबकि वर्ष 1991-92 के दौरान 861.40 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए थे। इस ऋण में से 78 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र, 15.8 प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र तथा 6 प्रतिशत तृतीय क्षेत्र के लिए था। 31 मार्च, 1993 को दिए गए कर्जों तथा जमा धन का अनुपात 55.18 प्रतिशत था और 5,277 करोड़ रुपए के जमा के मुकाबले बकाया देशगी 2,912 करोड़ रुपए थी।

मैंने पहले भी कहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बाढ़-पीड़ितों को राहत देने के लिए राज्य सरकार को सहयोग प्रदान किया है। बैंकों में बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के सुधार, मुरम्मत तथा पुनिर्माण के लिए ऋणों की व्यवस्था की। हमें विश्वास है कि बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं राज्य में विकास की गति को तीव्र करने के लिए राज्य सरकार को पूरा समर्थन देती रहेंगी।

पर्यटन

हरियाणा ने पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, हालांकि राज्य में कोई भी प्राकृतिक पर्यटन-स्थल नहीं है। राज्य में 43 पर्यटन केन्द्र हैं। चालू वर्ष के दौरान राज्य ने एक लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों तथा 42 लाख से अधिक देशी पर्यटकों का सत्कार किया है। इस वर्ष पंचकूला तथा फतेहाबाद में दो नये पर्यटन केन्द्रों का निर्माण किया गया है। हिसार तथा यमुनानगर में दो और ऐसे पर्यटन केन्द्र निर्माणाधीन हैं। एक अलग प्रकार का पर्यटन केन्द्र "एथनिक इण्डिया" सोनीपत के निकट राई में बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1994-95 में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 3.20 करोड़ रुपये खर्च

[श्री भागे राम गुप्ता]

किए जाएंगे । हम इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और अब तक 14 निजी पर्यटन केन्द्र खुल चुके हैं ।

वन और पर्यावरण

वनों के अधीन और अधिक क्षेत्र को लाने के लिए राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रों में अनेक स्कीमें चलाई जा रही हैं । वर्ष 1994-95 के दौरान ई० ई० सी० द्वारा लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत की "बंजर भूमि वानिकी और कृषि वानिकी" परियोजना के परखे और अनुमोदित किये जाने की सम्भावना है । वानिकी कार्यों को और बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1994-95 की वार्षिक योजना में 29.18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

पर्यावरण संरक्षण और परिवेश व्यवस्था पर पिछले कुछ वर्षों से विशेष ध्यान दिया जा रहा है । राज्य में वर्ष 1984 में पर्यावरण विभाग बनाया गया था, जो राज्य में परिवेश संतुलन के संरक्षण और सुधार के लिए अनेक कार्य कर रहा है । राज्य स्तरीय परामर्शी प्रयोगशाला एवं आम एफ्लुएंट शोधन संयन्त्र कुंडली उद्योग सम्पदा में स्थापित किए गए हैं । इसी प्रकार के आम एफ्लुएंट शोधन संयंत्र वर्ष 1994-95 के दौरान अम्बाला, मूरथल और जींद में स्थापित किये जायेंगे । पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और वन्यप्राणी संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सरकार का राज्य के मण्डलीय मुख्यालयों में 4 विशेष पर्यावरण अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव है । वर्ष 1994-95 में पर्यावरण संरक्षण के लिए 1.10 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है ।

सड़क परिवहन

हरियाणा राज्य परिवहन देश के सर्वोत्तम परिवहन उपक्रमों में से है । वर्ष 1993-94 के दौरान परिवहन विभाग के कार्यचालन में ईंधन क्षमता, लोड फैक्टर और प्रति किलोमीटर आय में और भी सुधार हुआ है। बस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं, जैसे डिपो का कम्प्यूटरीकरण केन्द्रीय इंजन-ओवर हालिंग वर्कशाप की स्थापना, वर्कशापों में फ्लोटिंग लाइन असैम्बली की व्यवस्था, बसें धोने के लिए स्वचालित मशीनें लगाना और प्रदूषण नियन्त्रण उपकरों की व्यवस्था आदि । वर्ष 1994-95 के दौरान 548 बसों को बदलने के लिए 34.73 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है । माननीय सदस्यों को याद होगा कि योजना आयोग इस बात से सहमत नहीं हो रहा है कि राज्य परिवहन उपक्रमों की बसों की संख्या में वृद्धि की जाये । जनता की स्थानीय परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए हम ने गत वर्ष बेरोजगार युवकों को सहकारी समितियों

की लिंक मार्गों पर बसें चलाने के लिए बस परमिट देने का निर्णय लिया है। ऐसे परमिट देने सम्बन्धी प्रक्रिया को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है और शीघ्र ही ये सहकारी समितियां अपनी बसें चलाना आरम्भ कर देंगी।

राज्य में 68 आधुनिक बस अड्डे हैं और इस समय 9 बस अड्डे निर्माणाधीन हैं। हमारा शीघ्र ही कलानौर, रोहतक बाईपास, अम्बाला छावनी और राजौंद में बस अड्डों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण विकास

सरकार यह मानती है कि यद्यपि हमें कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास जारी रखने हैं, तथापि केवल इसी से ग्रामीण निर्धनता दूर नहीं हो सकती। हमने ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए अनेक क्षेत्रीय कार्यक्रम आरम्भ किये हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसर जुटाने पर हम विशेष बल दे रहे हैं। इन में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और हाल ही में आरम्भ की गई रोजगार आश्वासन योजना स्कीम शामिल हैं। भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान दिसम्बर, 1993 तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 14,828 परिवारों को सहायता दी गई है और ट्राईसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत स्व-रोजगार के लिए 3,380 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किया गया और जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभकारी रोजगार के 12.06 लाख श्रम दिवस जुटाए गए हैं। राज्य में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास की गति को काफी तेज करने के लिए वर्ष 1994-95 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के लिए कुल 74.97 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया जा रहा है जो कि इन गतिविधियों हेतु चालू वर्ष के 51.77 करोड़ रुपये के परिव्यय से लगभग 45 प्रतिशत अधिक है।

शहरी विकास

हमारी सरकार शहरी क्षेत्रों के अनुरक्षण और विकास की ओर भी इतनी ही जागरूक है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण शहरी क्षेत्रों के योजनाबद्ध एवं एकीकृत विकास का कार्य कर रहा है। वर्ष के दौरान दिसम्बर, 1993 तक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने शहरी विकास निर्माण कार्यों पर 44.45 करोड़ रुपये खर्च किए और विभिन्न सम्पदाओं में 8 रिहायशी तथा 3 औद्योगिक सैक्टर बनाए। विभिन्न नगरपालिकाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए चालू वर्ष के दौरान 6.55 करोड़ रुपये के उपबन्ध के मुकाबले वर्ष 1994-95 में 7 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया जा रहा है। गंदी बस्तियों के सुधार की स्कीम को लागू करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और वर्ष 1994-95 में गंदी बस्तियों में रहने वाले 48,190 लोगों की सहायता करने के लिए 2.53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया

[श्री मांगे राम गुप्ता]

गया है । चालू वर्ष में 3 नई स्कीमें लघु एवं मध्यम दर्जे के नगरों का एकीकृत विकास, निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं तथा शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार जुटाने की स्कीम को शुरू किया गया है । वर्ष 1994-95 के दौरान इन स्कीमों के लिए 2.90 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है । नेहरू रोजगार योजना के लिए वर्ष 1994-95 में उपबन्ध को बढ़ाकर 4.40 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

पिछड़ा क्षेत्र विकास

मेवात क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 1980 में गठित मेवात विकास बोर्ड इस क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए लगातार कार्य कर रहा है । वर्ष 1992-93 तक इस प्रयोजन के लिए 28 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है । मेवात क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 1994-95 में 3.74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है ।

अम्बाला जिले के मोरनी, पिंजौर, बरवाला, रायपुर रानी और नारायणगढ़ खण्डों तथा यमुनानगर जिले के छछरौली, सढ़ौरा तथा बिलासपुर खण्डों में पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों के शीघ्र और एकीकृत विकास के लिए मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में शिवालिक विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इस प्रयोजन के लिए चालू वर्ष के दौरान 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है व वर्ष 1994-95 के दौरान 3 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया जा रहा है ।

विकेन्द्रीकृत योजना

माननीय सदस्य जानते ही हैं कि पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार "विकेन्द्रीकृत योजना स्कीम" को लागू कर रही है । स्थानीय स्कीम के विकास कार्य जिला स्तर पर किए जाते हैं । स्कीमें जिला योजना बोर्ड द्वारा तैयार की जाती हैं जिनमें अध्यक्ष के तौर पर उपायुक्त, स्थानीय अधिकारी, जन नेता, विधायक तथा सांसद शामिल होते हैं । इन स्कीमों को तैयार करने में जनता के प्रतिनिधियों को और नजदीक से शामिल करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे विकास कार्य स्थानीय विधायक के निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे । इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान किया जाएगा । मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने में माननीय सदस्य अपने चुनाव क्षेत्रों के अत्यधिक जरूरी विकास कार्य करवा पाएंगे ।

रोजगार

सभी विकास कार्यों का एक मुख्य उद्देश्य रोजगार जुटाना है । हमारी सरकार संगठित तथा असंगठित, दोनों क्षेत्रों में विशेषकर सामाजिक तथा आर्थिक तौर पर

पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने के लिए वचनबद्ध है। नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, 'ट्राइसेम और 'डाकरा जैसी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से इस दिशा में भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। आठवीं योजना के दौरान "एक परिवार एक रोजगार" स्कीम के अन्तर्गत रोजगार के पांच लाख अवसर जुटाने का हमारा प्रस्ताव है। वर्ष 1992–93 के दौरान, प्राइवेट सैक्टर में 31,526, स्वरोजगार सैक्टर में 73,794 तथा श्रम रोजगार सैक्टर में 66,941 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया और 7000 से भी अधिक व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया। बेरोजगारी भत्ता स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1994–95 के दौरान 3.35 करोड़ रुपये 35,000 पात्र बेरोजगार व्यक्तियों में वितरित किए जाएंगे। बरवाला में एक नया ग्रामीण रोजगार केन्द्र खोल कर और महेन्द्रगढ़ तथा नारायणगढ़ में दो रोजगार केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर राज्य के 95 रोजगार केन्द्रों के वर्तमान नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा रहा है। खेती बाड़ी की मंदी के दौरान 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए कम से कम 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने नवम्बर, 1993 में "रोजगार आश्वासन स्कीम" शुरू की। भारत सरकार के साथ भागीदारी आधार पर राज्य के 44 खण्डों में यह स्कीम लागू की जा रही है। वर्ष 1993–94 में इस के लिए 16.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है और वर्ष 1994–95 में 30.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

औद्योगिक प्रशिक्षण

उद्योगीकरण का लाभ तब तक पूरी तरह से नहीं उठाया जा सकता जब तक राज्य में उद्योगों के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध न हों। 140 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की एक व्यापक स्थापना द्वारा 70 से ज्यादा ट्रेडों और व्यवसायों में प्रति वर्ष 10,000 युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। शिवालिक विकास बोर्ड के तत्वावधान में कालका, बरवाला और सढ़ौरा में तीन नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। वर्ष 1994–95 के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए 7.62 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। हायर सैकण्डरी शिक्षा को व्यावसायिक बनाने के लिए 1993–94 में 5.27 करोड़ रुपये के योजनागत उपबन्ध को बढ़ाकर वर्ष 1994–95 के लिए 6.46 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आगामी वर्ष में 10 नये व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाएंगे।

तकनीकी शिक्षा

मानव संसाधन विकास के एक अहम अंग के रूप में सरकार तकनीकी शिक्षा को सदैव महत्व देती रही है। अतः हम ने प्रत्येक जिला में कम से कम एक पालिटैक्निक स्थापित करने का निर्णय लिया है। जिला गुड़गांवा में मानेसर में एक राजकीय पालिटैक्निक स्थापित करने की योजना है जिसके लिए भारत सरकार से अनुमोदन

[श्री मांग राम गुप्ता]

प्राप्त हो गया है । हिसार में राज्य का तीसरा इंजीनियरिंग कालेज खोलने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और दो विषयों में अस्थायी तौर पर शिक्षा आरम्भ भी कर दी गयी है । राजकीय और गैर-सरकारी पालिटैक्निक संस्थानों को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए एक विश्व बैंक परियोजना लागू की जा रही है । हिसार, फरीदाबाद, डबावड़ और नारनौल में चार नये पालिटैक्निक संस्थान 32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित किये जा रहे हैं । वर्ष 1994-95 के दौरान तकनीकी शिक्षा के लिए 38.97 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

हम नयी प्रौद्योगिकी के लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए राज्य के सभी पालिटैक्निक संस्थानों में "सामुदायिक पालिटैक्निक" स्कीम शुरू कर रहे हैं । राज्य में 8 पालिटैक्निक संस्थानों को 'सामुदायिक पालिटैक्निक' घोषित किया गया है ये संस्थान विज्ञान तथा तकनीकी का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य करेंगे ।

सरकार ने 80 लाख रुपये की लागत से राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के सहयोग से हिसार में उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है । चालू वर्ष के दौरान "प्राकृतिक साधन आंकड़ा प्रबन्ध प्रणाली" नामक एक एक परियोजना शुरू की गई है ।

शिक्षा

मानव संसाधनों के प्रभावी विकास के लिए सरकार ने शिक्षा को उच्चतम प्राथमिकता दी है । यह महसूस करते हुए कि जीवन के स्तर में सुधार और प्रतिष्ठा के लिए शिक्षा और साक्षरता आवश्यक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्राथमिक शिक्षा को सब लोगों तक पहुंचाने और पूर्ण साक्षरता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित किया गया है । ग्राम स्तर पर इस कार्य के लिए ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया गया है । बीच में स्कूल छोड़ कर जाने वाले और स्कूल न जाने वाले बच्चों को दाखिल करने में विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रत्येक खण्ड में एक पंचायत और एक विद्यालय चुना जाता है । ऐसी 124 पंचायतों और विद्यालयों को पांच-पांच हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया । प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले और स्कूल छोड़ जाने वाले अधिक से अधिक बच्चों को दाखिल करने के लिए विशेष दाखिला अभियान चलाया गया था । इसके परिणामस्वरूप, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 22.40 लाख हो गई है । 900 से अधिक जे0बी0टी0 अध्यापकों को नियुक्त किया गया है और 1256 जे0बी0टी0 अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालयों में मुख्या-ध्यापक के रूप में पदोन्नत किया गया ।

अम्बाला यमुनानगर, जींद, भिवानी, रोहतक और सिरसा जिलों में पूर्ण साक्षरता परियोजनाएं चलाई जा रही हैं । इन परियोजनाओं को मार्च, 1994 तक पूर्ण करने

का प्रस्ताव है। इसके बाद उत्तर–साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पानीपत जिला में उत्तर–साक्षरता अभियान चल रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शेष जिलों में उपयुक्त वातावरण बनाने का अभियान शुरू किया जा चुका है।

वर्ष के दौरान, 31 प्राथमिक, 32 मिडल और 22 उच्च विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है। अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए अध्यापकों के 150 पद व प्राध्यापकों के 250 पद भी बनाये गये हैं। वर्ष 1994–95 के दौरान 50 प्राथमिक और 25 मिडल विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया जायेगा और 200 अध्यापकों तथा 250 प्राध्यापकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए 8 जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है और वर्ष 1994–95 के दौरान 4 अन्य ऐसी संस्थाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य में 9 जवाहर नवोदय विद्यालय चल रहे हैं और 3 ऐसे अन्य विद्यालय कुरुक्षेत्र, गुड़गांव और रेवाड़ी जिलों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 1994–95 के दौरान 2 और जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

विद्यालय भवनों की मरम्मत करने तथा अतिरिक्त श्रेणी कक्षों के निर्माण के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। वर्ष 1993–94 के दौरान 401 विद्यालय भवनों की मरम्मत तथा 287 श्रेणी कक्षों का निर्माण क्रमशः 1.29 करोड़ रुपये तथा 2.14 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। विद्यालय भवनों की मरम्मत तथा निर्माण की स्कीम आगामी वर्ष भी जारी रखी जाएगी।

प्राथमिक तथा विद्यालय शिक्षा को महत्वपूर्ण समझने के साथ–साथ, सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा को अधिक गतिशील तथा गहन बनाने के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। तदनुसार चालू वर्ष के दौरान एक नया राजकीय महाविद्यालय बरवाला में व दो नये गैर–सरकारी महाविद्यालय पंजोखड़ा (अम्बाला) तथा समालखा (पानीपत) में खोले गये हैं। वर्ष 1994–95 में तोशाम (भिवानी) में गैर–सरकारी महाविद्यालय खोलने के लिए भी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूर्ण रूप से बदला गया है ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। प्राध्यापकों और शिक्षा–प्रशासकों के लिए विभिन्न कार्यशालाएं तथा गोष्ठियों का आयोजन किया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सुयोग्य प्राध्यापकों की भर्ती के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत राष्ट्र स्तरीय पात्रता परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण अध्यापकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए प्राध्यापकों के 25 पद बनाए गए हैं तथा 200 प्राध्यापकों को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उच्चतर शिक्षा निदेशालय में एक "महिला कक्ष" की स्थापना की गई है। सरकार विश्व विद्यालय शिक्षा की ओर भी इतना ही ध्यान दे रही है।

[श्री मांगे राम गुप्ता]

स्वास्थ्य

सरकार 2000 ई0 तक "सभी के लिए स्वास्थ्य' के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। 134 स्वास्थ्य उप-केन्द्रों, 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 4 हस्पतालों का निर्माण करके स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे राज्य में सभी को 5–6 किलोमीटर के घेरे में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी। परिवार कल्याण और जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रमों के परिणाम अच्छे रहे हैं और जन्म दर और शिशु मृत्यु दर कम हो कर क्रमशः 31.9 और 75 प्रति हजार हो गई है, जो 2000 ईस्वी तक क्रमशः 21 और 60 प्रति हजार तक और कम हो जाने की सम्भावना है। हमारा प्रस्ताव है कि माता व शिशु की देख–रेख के लिए प्रसव व उससे पूर्व और पश्चात् की रोग निरोधी तथा प्रतिरक्षण सेवाएं बढ़ाई जाएं। ओरल री–हाईड्रेशन थैरपी और गम्भीर श्वास संक्रमण नियंत्रण सम्बन्धी दो नये कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। एक राज्य स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान, पंचकूला में स्थापित किया गया है। एड्स के बढ़ते हुए खतरे पर काबू पाने के लिए चालू वर्ष के दौरान 44.48 लाख रुपये की राशि खर्च की जा रही है ताकि लोगों को, विशेष कर रोग सम्भावित वर्गों को, इस के प्रति सचेत किया जा सके।

औद्योगिक कामगारों को भी अधिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। इसके लिए भिवानी में 50 बिस्तर का ई0 एस0 आई0 हस्पताल और रोजका–मेव, गुड़गांव में एक ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी खोली जाएगी। रोहतक मैडिकल कालेज तथा हस्पताल में तपेदिक और छाती की बीमारियों के लिए 50 बिस्तरों वाला वार्ड और अति विशिष्ट सेवाओं के लिए एक नया खंड बनाया जा रहा है जहां चार उन्नत क्षेत्रों में अति विशिष्ट सेवाएं प्रदान की जायेंगी। पंचकूला में हरियाणा वैकल्पिक चिकित्सा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद् स्थापित की गई है ताकि आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक प्रणालियों जैसी वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहन दिया जा सके। इस वर्ष 1993–94 के दौरान 10 नई आयुर्वेदिक डिस्पैंसरियां और वर्ष 1994–95 के दौरान ऐसी पांच नई डिस्पैंसरियां खोल रहे हैं। श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं हस्पताल, कुरूक्षेत्र के भवन के निर्माण–कार्य में लगातार प्रगति हो रही है।

जल सप्लाई और सफाई

अच्छी सेहत के लिए स्वच्छ पेय जल बहुत जरूरी है। राज्य के सभी 6,745 गांवों में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध करवाने के बाद अब हमने गांवों में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता बढ़ाने के काम पर जोर दिया है। चालू वर्ष तथा अगले वर्ष 800 ऐसे गांवों को इस योजना के तहत लाया जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक गांवों की सभी ढाणियों को पेय जल की सुविधाएं जुटा दी जायेंगी।

वर्ष 1994-95 के लिए इस प्रयोजनार्थ 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष के दौरान 9 बड़े गांवों में घरों में पानी के कनैक्शन देने के लिए मौजूदा जल सप्लाई को बढ़ाया जाएगा। अगले वर्ष तीन और बड़े गांवों में इस प्रोग्राम को लागू किया जाएगा। 42 करोड़ रुपए की लागत से किफायती ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के तहत एक लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों में पानी वाले फ्लश शौचालय बनाए गए हैं।

सरकार शहरी क्षेत्रों में भी जल सप्लाई और सफाई की जरूरत के प्रति पूरी तरह जागरूक है। शहरों में इन सुविधाओं को सुधारने के लिए परिव्यय में 16.5 प्रतिशत की बढ़ौतरी की गई है। बहादुरगढ़ और गुड़गांव शहरों को पेय जल सप्लाई करने के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से एक अलग जल वाहक नहर का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होने की सम्भावना है। तीन शहरों में बरसाती पानी के निकास के लिए नालियों की और हिसार में सालिड वेस्ट को निपटाने की व्यवस्था के लिए भी कार्य आरम्भ किया गया है। सरकार ने 133.47 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी की सीमा के साथ लगते सात शहरों में पूर्ण सफाई और मलशोधन सुविधा का प्रबन्ध करने का एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम भी शुरू किया है। यह प्रोग्राम केन्द्रीय सरकार के साथ मिल कर पूरा किया जाएगा और इसके लिए ओ०सी०ई०एफ० जापान द्वारा राशि जुटाई जाएगी।

कमजोर वर्गों का कल्याण

हमने समाज के कमजोर वर्गों, विशेषतया अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों, के विकास पर विशेष जोर दिया है। यद्यपि सामान्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में, जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, समाज के इन वर्गों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, तथापि हम समझते हैं कि उनके उत्थान के लिए और अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। साक्षरता को बढ़ावा देने और समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए अनेक स्कीमें लागू की जा रही हैं। अनुसूचित जाति की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता 5,000 रुपए से बढ़ा कर 10,000 रुपए कर दी गई है। इसी प्रकार, अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों के नजदीकी सम्बन्धियों को दी जाने वाली वित्तीय राहत मृत्यु के मामले में 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजनों को आवास-स्थल अलाट करने की स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1974 और 1982 के सर्वेक्षण में अंकित सभी पात्र व्यक्तियों को आवास-स्थल अलाट किए जा चुके हैं। इससे अनुसूचित जाति के लगभग 3 लाख परिवारों को लाभ पहुंचा है।

हरियाणा हरिजन कल्याण निगम अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम लागू कर रहा है। इस निगम की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई है।

[श्री मांगे राम गुप्ता]

अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 के कुल योजना परिव्यय का 13.9 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के परिवारों को सीधे लाभ देने वाली स्कीमों के लिए निर्धारित किया गया है।

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

माननीय सदस्य जानते हैं कि भूतपूर्व सैनिक हमारे समाज का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग हैं। हमारे राज्य का प्राय: हर नौवां व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक के परिवार से है। यह बात देश की सीमाओं की रक्षा में हरियाणा द्वारा दी गई महान सेवा की सूचक है। राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को अनेक रियायतें दी हैं। चालू वर्ष के दौरान उनके कल्याण के लिए 5 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जा रही है। भूतपूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा हेतु सरकार की चार नए जिलों, रिवाड़ी, कैथल, पानीपत और यमुनानगर, में जिला सैनिक बोर्ड स्थापित करने की योजना है। अस्थलबोहर में एक राज्य युद्ध स्मारक हाल बनाया जा रहा है। रोहतक में मातनहेल और रिवाड़ी में पालीगोदर में दो नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। रिवाड़ी में एक भर्ती कार्यालय खोलने का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा गया है।

महिलाएं बच्चे तथा समाज कल्याण

महिलाओं को अपनी शक्ति पहचानने में समर्थ बनाने व उन्हें विकास की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1992 में महिला तथा बाल विकास नाम से एक अलग विभाग स्थापित किया गया। वर्ष 1994-95 में यू० एन० एफ० पी० ए० की सहायता से सरकार 37.64 करोड़ रुपए की लागत से "महिला एम्पावरमैंट व समेकित विकास" परियोजना आरम्भ कर रही है। एकीकृत बाल विकास योजना, जोकि इस समय राज्य के 107 खण्डों में लागू की जा रही है, को राज्य के शेष सभी खंडों में लागू करने का निर्णय भी लिया जा चुका है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा देश में एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसके सभी ग्रामीण खंडों में एकीकृत बाल विकास योजना चालू है। इस योजना के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य के सभी आंगनवाड़ी वर्करों को शिक्षण प्रणाली तथा विद्यालय पूर्व की गतिविधियों में रिफ्रैशर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए "अंकुर" नाम की एक पुस्तिका पहले से ही तैयार की जा चुकी है।

वर्ष 1994-95 के दौरान 122.13 करोड़ रुपए के परिव्यय से सामाजिक रक्षा तथा सुरक्षा की अन्य स्कीमों को भी जारी रखा जाएगा। इन स्कीमों में निराश्रित एवं पीड़ित महिलाओं के लिए विशेष परियोजनाएं, अपंग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां, विधवाओं, अपंग व्यक्तियों और राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा भत्ता भी शामिल है।

आवास

सरकार शहरी तथा ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के लिए आवास की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह सजग है । तदनुसार हमने वर्ष 1994–95 में आवास के प्रावधान को बजट अनुमान 1993–94 की तुलना में 75 प्रतिशत बढ़ा दिया है । चालू वर्ष के लिए उपबन्ध को भी 20 प्रतिशत बढ़ाकर 33.67 करोड़ रुपये कर दिया गया है । आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए ऋण योजना के अन्तर्गत इस वर्ष बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए हुडको द्वारा 8.71 करोड़ रुपए के राहत ऋण दिए गए ।

राज्य में विभिन्न स्थलों पर आवास यूनिटों के निर्माण के लिए चालू वर्ष के दौरान आवास बोर्ड द्वारा 84.36 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे । बोर्ड की, हुडको के सहयोग से कम लागत वाली निर्माण तकनीकों का प्रयोग करते हुए 500 मकान बनाने की भी योजना है ।

राजस्व प्रशासन

भू-अभिलेखों की व्यवस्था करना राजस्व प्रशासन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से है । हमारी सरकार ने भूमि तथा राजस्व प्रशासन के आधुनिकीकरण और सुधार की ओर काफी ध्यान दिया है । रिवाड़ी जिले में भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करने की एक पायलट परियोजना शुरू की गई है । भू-अभिलेखों की कम्प्यूटर व्यवस्था करने के लिए रोहतक, हिसार, सिरसा व गुड़गांव जिलों में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति भारत सरकार से मिल चुकी है । राजस्व अभिलेखों की सुरक्षा के लिए वर्ष 1993–94 में पांच रिकार्ड रूमों का निर्माण किया जा रहा है। हिसार में लघु सचिवालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । यमुनानगर, कैथल और रिवाड़ी में लघु सचिवालय बनाने का कार्य वर्ष 1994–95 में शुरू किया जाएगा । राज्य में 472 पटवारखाने मौजूद हैं और 242 अन्य पटवारखाने निर्माणाधीन हैं । जनता की सुविधा के लिए सभी 3,136 पटवार सर्कलों में पटवारखाने बनाए जाने का प्रस्ताव है ।

खजाने

हरियाणा में वित्तीय व्यवस्था का स्तर हमेशा बहुत बढ़िया रहा है । वित्तीय व्यवस्था को और कुशल बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी खजानों का कम्प्यूटीकरण किया जा रहा है । आठ नए उप–खजानों को स्थापित करके राज्य में विद्यमान 18 जिला स्तरीय खजानों व 77 उप–खजानों के नैटवर्क को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है।

प्राईवेट लाटरियों पर प्रतिबन्ध

चालू वर्ष में लाटरी व्यापार में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है । जनसाधारण को बेईमान लाटरी आयोजकों के हाथों धोखे तथा ठगी की संभावना से बचाने के लिए

[श्री मांगे राम गुप्ता]

राज्य विधानमण्डल ने हरियाणा प्राईवेट लाटरी निषेध अधिनियम, 1993 बनाया है। इससे हरियाणा क्षेत्र में आयोजकों द्वारा चलाई जा रही सभी लाटरियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। अब केवल राज्य सरकारों द्वारा स्वयं आयोजित लाटरियां ही हरियाणा में बेची जा सकती हैं। राज्य का लाटरी विभाग राज्य में विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाने हेतु अनेक लाटरी स्कीमों को चला रहा है। विभाग का निवल लाभ 6.27 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से बढ़कर 14.55 करोड़ रुपए होने की आशा है।

सरकारी कर्मचारियों को रियायतें

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें प्रोत्साहन देने तथा उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए चालू वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारियों को अनेक रियायतें दी गई।

माननीय सदस्यगण जानते हैं कि भारत सरकार ने पांचवां वेतन आयोग गठित किया है और इस की सिफारिश पर अपने सभी कर्मचारियों को 100 रुपये प्रतिमास की अन्तरिम राहत दी है। हरियाणा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी प्रकार अन्तरिम राहत दे दी है। इस से राज्य के कोष पर 31 करोड़ रुपये का वार्षिक भार पड़ने की संभावना है। वर्ष 1992-93 के दौरान, राज्य सरकार ने 8 और 18 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने की स्कीम चलाई थी। इस स्कीम के स्थान पर ग्रुप 'सी' तथा ग्रुप 'डी' के सभी कर्मचारियों को 10 तथा 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के पश्चात् उच्चतर मानक वेतनमान देने की अधिक उदार स्कीम बनाई गई है। राज्य में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पहली अप्रैल, 1994 से 60 रुपये प्रतिमास की दर पर वर्दी भत्ता नकद दिये जाने की अनुमति दी गई है। कर्मचारियों को मिलने वाले निश्चित चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते की दर 45 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 60 रुपये प्रतिमास कर दी गई है। माननीय सदस्यगण इस बात को मानेंगे कि राज्य के वित्तीय संसाधनों की सीमा में ही हम ने सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त राहत दी है।

संशोधित अनुमान 1993-94

मैंने पहले भी कहा है कि चालू वर्ष के दौरान सरकार को भारी वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। बाढ़ से हुई क्षति, बाजार में मंदी और बिजली की चिन्ताजनक स्थिति से हमारी राजस्व प्राप्तियों पर प्रभाव पड़ा और परिणामस्वरुप अतिरिक्त खर्च हुआ। कर राजस्व 1993-94 के बजट अनुमानों में दर्शाए गए 2003.42 करोड़ रुपये से कम होकर संशोधित अनुमानों में 1893.98 करोड़ रुपये रह गया। इस में केन्द्रीय सरकार की सूचना अनुसार केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में

24.66 करोड़ रुपये, पथ कर के समाप्त होने के कारण वाहन करों के अन्तर्गत वसूली में 27 करोड़ रुपये और मदिरापान के विरुद्ध राज्य के कुछ भागों में आंदोलन होने से उत्पाद शुल्क में 46 करोड़ रुपये की मुख्य कमी हुई। खर्च पक्ष में, जल सप्लाई स्कीम के रख-रखाव पर 11 करोड़ रुपये, महालेखाकार के परामर्श के अनुसार पैंशन सम्बन्धी देयताओं में 18.65 करोड़ रुपय तथा ब्याज अदायगियों में 6.25 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। सरकारी कर्मचारियों को दी गई विभिन्न रियायतों, जिन का उल्लेख पहले किया जा चुका है, का भी राजकोष पर काफी बोझ पड़ा है। हमने राजस्व खर्च पर कड़ा नियंत्रण रखा है और जैसा कि माननीय सदस्य देखेंगे कि केवल अत्यधिक महत्व वाले अति आवश्यक मदों पर ही खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। कुल योजनागत परिव्यय को संशोधित अनुमानों में 920 करोड़ रुपये से घटा कर 831.46 करोड़ रुपये करना पड़ा। तथापि, यह सुनिश्चित कर लिया गया कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और निर्धारित क्षेत्रों के योजनागत परिव्यय को बरकरार रखा जाए ताकि राज्य के समूचे विकास पर इसका प्रभाव न पड़े।

पिछले वित्त वर्ष के दौरान सरकार की अच्छी वित्त व्यवस्था के परिणामस्वरुप वर्ष 1993–94 का आरम्भिक घाटा 54.27 करोड़ रुपये रहा जबकि बजट अनुमानों में यह घाटा 81.37 करोड़ रुपये अनुमानित था। बजट अनुमान 1993–94 को इस गरिमामय सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने के बाद उभरने वाले सभी हालात को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान दर्शाते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 74·48 करोड़ रुपये के प्रत्याशित घाटे से समाप्त होने की सम्भावना है, जबकि बजट अनुमानों में 87.32 करोड़ रुपये का घाटा परियोजित था। वित्तीय घाटा, चालू वर्ष के राज्य गृह उत्पाद के लगभग 3 प्रतिशत तक होने की संभावना है जोकि सीमाओं के अन्दर ही है।

बजट अनुमान 1994–95

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस गरिमामय सदन में वर्ष 1994–95 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1993–94 के संशोधित अनुमानों और 1994–95 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति दर्शाई गई है :–

(रुपये, करोड़ों में)

संघटक	लेखे 1992–93	बजट अनुमान 1993–94	संशोधित अनुमान 1993–94	बजट अनुमान 1994–95
1	2	3	4	5
I. अथ शेष				
(क) महालेखाकार के अनुसार	(–)0.14	(–)72.85	(–)57.59	(–)77.80

[श्री मांगे राम गुप्ता]

1	2	4	4	5
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(–)8.66	(–)81.37	(–)54.27	(–)74.48
(ग) खजाना बिलों में निवेश	1.50	1.50	17.42	17.42
II. राजस्व लेखा				
प्राप्तियां	2377.64	2872.99	3541.43	4305.82
खर्च	2379.34	2829.32	3533.22	4818.09
अधिशेष/घाटा	(–)1.70	(+)43.67	(+)8.21	(–)512.27
III. पूंजीगत खर्च	228.34	255.37	314.46	214.51
IV. लोक ऋण				
लिया गया ऋण	418.92	854.85	789.31	1157.61
भुगतान	163.47	546.82	400.62	813.67
निवल	(+)255.45	(+)308.03	(+)388.69	(+)343.94
V. कर्जे और पेशगियां				
पेशगियां	245.01	266.98	282.05	322.79
वसूलियां	31.01	34.36	34.90	457.02
निवल	(—)21400	(—)232.62	(—)247.15	(+)134.22
VI. लघु बचतें भविष्य निधि आदि				
निवल	(+)132.35	(+)114.29	(+)162.98	(+)215.08
VII. जमा तथा पेशगियां आरक्षित निधि और उचन्त तथा विविध				
निवल	(—)3.77	(+)14.05	(—)18.48	(+)36.96
VIII. प्रेषण				
निवल	(+)2.56	(+)2.00	0.00	0.00
IX. इतिशेष				
(क) महालेखाकार के अनुसार	(—)57.59	(—)78.80	(—)77.80	(—)74.43
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(—)54.27	(—)87.32	(—)74.48	(—)71.11
(ग) खजाना बिलों में निवेश	17.42	1.50	17.42	17.42

वर्ष 1994-95 रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार 74.48 करोड़ के घाटे से शुरु व 71.11 करोड़ रुपये के घाटे से खत्म होने की सम्भावना है। अतः वर्ष के खाते में, चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में हो रहे 20.21 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में वर्ष 1994-95 में 3.37 करोड़ रुपये का अधिशेष होना संभावित है। बजट अनुमानों में 1025.59 करोड़ रुपये की राज्य योजना व 231.76 करोड़ रुपये की केन्द्र चालित व अन्य विकास योजनाओं के परिव्यय समेत कुल 1257.26 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है।

वर्ष 1994-95 के राजस्व लेखे और पूंजीगत प्राप्तियों पर कुछ घटकों का प्रभाव होगा। लाटरी की टिकटों में चालू वर्ष में जबरदस्त वृद्धि हुई है। अतः 1994-95 में लाटरी की आय 940 करोड़ रुपये व खर्च 924.47 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिससे 15.53 करोड़ रुपये का निवल लाभ होगा। मैंने पहले भी कहा है कि सरकारी विभागों के बकाया बिजली बिलों के भुगतान हेतु 425 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र को रियायती बिजली सप्लाई के एवज् में बिजली बोर्ड को दी जाने वाली सबसिडी के बकाया 350 करोड़ रुपये के भुगतान का प्रावधान भी वर्ष 1994-95 के बजट अनुमानों में किया गया है। फलस्वरुप 1993-94 के संशोधित अनुमानों में दिखाए गए 8.21 करोड़ रुपये के राजस्व अधिशेष के मुकाबले 1994-95 के राजस्व लेखे में 512.27 करोड़ रुपये का घाटा प्रत्याशित है। बहरहाल, ग्रॉस आकड़ों से 1994-95 में राज्य के राजस्व लेखे की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लग पाता, क्योंकि लाटरी की आय व खर्च तथा कर्ज प्राप्तियों के समायोजन के लिए बिजली बोर्ड को बिलों की अदायगी काल्पनिक एंटरी है। ऐसी एन्ट्रियों का हिसाब करने के बाद नैट आधार पर 1994-95 में राजस्व घाटा 32.47 करोड़ रुपये रह जाता है। 1993-94 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1994-95 के बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियां ग्रॉस आधार पर 764.39 करोड़ रुपये व नैट आधार पर 328.48 करोड़ रुपये बढ़ी हैं। कर राजस्व में 1993-94 के संशोधित अनुमानों की तुलना में वर्ष 1994-95 के बजट अनुमानों में 11.35 प्रतिशत की वृद्धि है, यद्यपि भिन्न करों के लिए भिन्न वृद्धि दरें अपनाई गई हैं। केन्द्रीय करों में हिस्सा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा दिये गये संकेतों के अनुसार रखा गया है। नान टैक्स राजस्व में चालू साल के संशोधित अनुमानों की तुलना में 512.39 करोड़ रुपये की वृद्धि 1994-95 के बजट अनुमानों में मौजूद है। राजस्व प्राप्तियों के अनुमान प्रवृत्ति के आधार पर लगाए गए हैं व प्राप्तियों के भिन्न शीर्षकों के लिए भिन्न मापदण्ड अपनाए गए हैं। सम्भव है कि अर्थव्यवस्था में निहित लचीलेपन व प्रत्याशित बढ़ोतरी से राजस्व में और वृद्धि हो पाये। गैर-योजना खर्च का अनुमान लगाने में प्रायः योजना आयोग के अनुदेशों और नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों को आधार माना गया है। आवश्यक खर्च का प्रावधान करने के पश्चात् योजनेतर राजस्व खर्च को कम से कम रखा गया है।

[श्री मांगे राम गुप्ता]

वर्ष 1994–95 के बजट अनुमानों में सातवीं पंचवर्षीय योजना तक पूरी की गई योजना स्कीमों के रख-रखाव हेतु 57.25 करोड़ रुपये व खालों को पक्का करने पर हुए खर्च में लाभ-भोगियों के हिस्से की प्रतिपूर्ति हेतु एम० आई० टी० सी० के लिए 14.73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जैसे कि पहले कहा गया है कि कृषि क्षेत्र को रियायती बिजली सप्लाई की प्रतिपूर्ति के लिए बोर्ड को 105 करोड़ रुपये की नकद सबसिडी देने का प्रावधान किया गया है। सिंचाई व जन-स्वास्थ्य विभागों और एम० आई० टी० सी० द्वारा वर्तमान बिजली बिलों के भुगतान हेतु 48.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चुनाव आयोग के अनुदेशों के अनुसार मतदाताओं के पहचान पत्र बनाने के लिए 26 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है। सरकारी कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते की जनवरी व जुलाई 1994 से देय होने वाली दो किश्तों के लिए 64.78 करोड़ रुपये व 1991–92 व 1992–93 वित्तीय वर्षों के बोनस की अदायगी के लिए 54.80 करोड़ रुपये का उपबन्ध बजट अनुमान 1994–95 में किया गया है।

माननीय सदस्य देखेंगे कि 1994–95 के बजट अनुमानों के अनुसार 1157.61 करोड़ रुपये का सार्वजनिक ऋण राज्य द्वारा लिया जाएगा। 813.67 करोड़ रुपये के भुगतान के कारण निवल सार्वजनिक ऋण 343.94 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। इन में केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की ओर से राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले 27.12 करोड़ रुपये के बाजारी ऋण भी शामिल हैं।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि देश के कई अन्य राज्यों में योजना खर्च का एक बड़ा हिस्सा कर्ज द्वारा पूरा किया जाता है। लेकिन हमारे राज्य में ऐसा नहीं है। बहरहाल हमारे राज्य का कुल ऋण भार बढ़ रहा है। महालेखाकार, हरियाणा के लेखों के अनुसार 31 मार्च, 1993 को राज्य पर ऋणों का कुल भार 3768.51 करोड़ रुपये था जोकि हमारी 31 मार्च, 1992 की 3300.46 करोड़ रुपये की ऋण देयता से 14.18 प्रतिशत अधिक है। प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य के ऋण भार में 585.99 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। अतः 31 मार्च, 1994 को राज्य का कुल ऋण भार 4354.50 करोड़ रुपये हो जाएगा जो 31 मार्च 1993 के मुकाबले 15.6 प्रतिशत अधिक होगा। यह भार 31 मार्च, 1995 तक 12.9 प्रतिशत की दर से बढ़कर 4918.11 करोड़ रुपये होने की संभावना है। यह पूंजी मुख्यतः पूंजीगत निवेश व उत्पादन शील सम्पत्ति बनाने के लिए है व इन पर ब्याज अदायगी का काफी खर्च होता है। चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में ब्याज अदायगी का भार, अधिक ऋण प्राप्तियों के कारण बजट अनुमान 1994–95 में

21.5 प्रतिशत बढ़ गया है । बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 1994-95 के दौरान 535.05 करोड़ रुपये का ब्याज अदा किया जाएगा ।

मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार और अनेक राज्यों का वित्तीय घाटा काफी अधिक है । वित्तीय घाटे को उचित सीमाओं में रखने की आवश्यकता को अब देश में सभी महत्व देने लगे हैं । राज्य गृह उत्पाद के अनुपात में हरियाणा का वित्तीय घाटा वर्ष 1994-95 के दौरान 2.8 प्रतिशत तक होने की संभावना है । राज्य के वित्तीय घाटे को और कम करने के निरंतर प्रयास किए जाएंगे ।

माननीय सदस्य जानते ही हैं कि अर्थव्यवस्था में कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में लाइसैंस समाप्त करके और नियंत्रण हटाकर उदार नीति अपनाई है । विभिन्न विभागों द्वारा राज्य के प्रवेश स्थानों अथवा अन्य स्थानों पर बनाये गये बैरियर, जो हालांकि कर की चोरी और सामान एवं वस्तुओं के गैर-कानूनी आवागमन को रोकने के आवश्यक उद्देश्य से ही बनाए गए थे, तथापि इन से यातायात में रुकावट आती है, कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उत्पादकता में कमी आती है तथा कीमती समय और ईंधन बर्बाद होता है । केन्द्र सरकार की नीति का अनुसरण करते हुए सरकार ने हरियाणा में ऐसे सभी नाकों को हटाने का निर्णय लिया है । इसके परिणामस्वरूप बची जन शक्ति और अन्य साधनों को कर-चोरी रोकने के लिए विभागीय तंत्र को सशक्त बनाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा । हम समझते हैं कि इस से देश में एकीकृत आर्थिक वातावरण बनने की शुरुआत होगी ।

सरकार व्यापार तथा उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक है तथा इनके प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत कर रही है । उपभोक्ताओं व छोटे व्यापारियों का विशेष ध्यान रखते हुए कर प्रणाली में सुधार और रैशनेलाईजेशन के लिए सरकार द्वारा गहन प्रयास किये जा रहे हैं । सरकार परेशानी का कारण बनने वाले सभी प्रोसीजरों में सुधार लाने के लिए भी सदैव तत्पर रहती है । इसी प्रकार के कुछ कदम हमने उठाए हैं जिन के विषय में बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है । 5 लाख रुपये से कम बिक्री वाले छोटे व्यापारियों के लाभ के लिए एक स्कीम प्रस्तावित है जिनके अन्तर्गत उन्हें घोषित बिक्री के आधार पर देय बिक्री कर की एकमुश्त अदायगी की सुविधा दी जाएगी । इस सुविधा से छोटे व्यापारी विस्तृत लेखा-जोखा रखने के झंझट से बच जाएंगे व निर्धारण अधिकारियों को भी बड़े व्यापारियों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने की फुरसत मिलेगी । इसी प्रकार की सुविधा जिले के अन्दर नियत मार्गों पर यात्री सेवाओं के आयोजकों को यात्री कर की अदायगी के लिए भी दी जाएगी । हमारे जन समुदाय के निर्धन वर्ग को राहत देने के लिए सरकार का सभी दालों की चूरी व छिलके की, जोकि पशु चारे के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, बिक्री कर से छूट देने का प्रस्ताव है । तेल

[श्री मांगे राम गुप्ता]

व तिलहन के व्यापारी सरकार से इन चीजों पर बिक्री कर प्रणाली की रैशनेलाईजेशन की मांग करते रहे हैं । सरकार इस प्रकार की रैशनेलाईजेशन से राज्य के राजस्व पर होने वाले प्रभाव की जांच रही है । बहरहाल हमने तिलहन की अन्तर्राज्यीय बिक्री के लिए "सी" फार्म भरने की शर्त को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है । मैं यहां कहना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य वर्तमान कर कानूनों को सख्ती, बिना भेदभाव व प्रभावशाली तरीके से लागू करके राज्य के लिए अधिक राजस्व प्राप्त करना है, न कि नए कर लगाना अथवा कराधान की दरों में वृद्धि करना । मेरा इस बजट में किसी प्रकार के नए कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बजट में घाटा कम से कम रखा गया है और यह उपयुक्त सीमा के अन्दर ही है । राज्य सरकार ने "संसाधन और किफायत पर मंत्रिमण्डलीय उप समिति" का गठन किया है जिसने काफी आरंभिक कार्य कर लिया है । हमें आशा है कि खर्चों में और अधिक कटौती कर के, कर-आधार को व्यापक बना कर, कर-प्राप्तियों में सुधार कर के तथा करों की चोरी को रोक कर हम घाटा और भी कम कर पाएंगे । हम योजनेतर खर्च में भी कमी करने का यत्न करेंगे और मुझे विश्वास है कि वर्ष 1994-95 की वार्षिक योजना में सभी विकास कार्यक्रमों को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाएगा । इस उद्देश्य के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों तथा हरियाणा की जनता से सहयोग और सहायता की अपेक्षा करता हूं ।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं बजट अनुमान 1994-95 सदन के विचार तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

जय हिन्द ।

Mr Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 8th March, 1994.

*16.25 (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday, the 8th March, 1994.)

25688—H.V.S.—H.G.P.,—Chd.